आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650

इंदौर, शुक्रवार 19 दिसंबर 2025

■ वर्ष : 5 ■ अंक : 46

■ पृष्ठ : 6 ■ मूल्य : 2

dainikindoresanket.com
dainikindoresanket
dainikindoresanket
dainikindoresanket24@gmail.com

सांध्य दैनिक

इंदौर संकेत

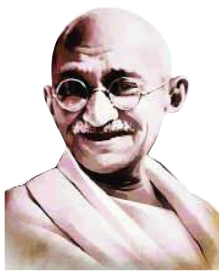

राष्ट्रपिता को नमन...

अंदर के पन्नों पर...

इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन को हरी झंडी

पेज-2

अहमदाबाद में निर्णायक मुकाबला आज

पेज-5

ट्रैफिक ई-चालान के नाम पर डिजिटल फ्राड का नया तरीका

पेज-6

मुख्यमंत्री पर कैलाश विजयवर्गीय के बयान से शीत लहर में भी गरमाई भाजपाई राजनीति

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंत्रिमंडल के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गत दो-तीन दिनों में बयानों को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा में मुख्यमंत्री के सूटबूट और अपने आपको गरीब बताने वाले बयान और इंदौर, भोपाल के मास्टर प्लान को देखने का मुख्यमंत्री को समय न मिलने की सार्वजनिक बयानबाजी की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि काफी समय से प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल सभी वरिष्ठ मंत्री अपने अधिकारों को लेकर कश्मकश में दिख रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय के दोनों ही बयान प्रदेश के सभी मंत्रियों की व्यथा को बयां कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अगर इन मंत्रियों के करीबियों से हुई चर्चा को माने तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सभी मंत्रियों पर अफसरशाही के नाम से लगाम लगा रखी है। हालांकि डॉ. मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय के बीच सार्वजनिक तौर पर जो नजदीकिया दिखाई देती है, उसको लेकर मंत्रियों के करीबियों के बयानों से इश्तफाक नहीं रखा जा सकता है।

बहरहाल प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर का भविष्य मुख्यमंत्री के बीच अटका हुआ है। यह स्वीकारोक्ति किसी विपक्षी नेता की नहीं, बल्कि सरकार के

वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ शब्दों में कहा कि दोनों शहरों के मास्टर प्लान बनकर तैयार हैं, मुख्य सचिव इन्हें देख चुके हैं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की व्यस्तताओं के कारण अब तक इन्हें अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाई है।

'सूट-बूट' टिप्पणी से जुड़ता सियासी संकेत

इस बयान से एक दिन पहले विधानसभा के विशेष सत्र में कैलाश विजयवर्गीय ने एक और टिप्पणी कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र करते हुए जब बात वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आई, तो विजयवर्गीय ने कहा कि अभी 20-20 क्रिकेट मैच चल रहा है। कप्तान सूर्यकुमार मैदान में उतरते ही सब खिलाड़ियों को किट बांट देते हैं। हमारे कप्तान ऐसे हैं कि खुद सूट-बूट में आ गए। हम सब गरीब ऐसे ही बैठे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे केवल व्यंग्य नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर असंतोष के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक मायने

विश्लेषकों का मानना है कि विजयवर्गीय के ये बयान साधारण प्रशासनिक जानकारी नहीं, बल्कि सोची-समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं। वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विभाग में विकास को लेकर कोई रुकावट नहीं है। यदि योजनाएं अटकी हैं, तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। भाजपा के भीतर सत्ता संतुलन को लेकर जो असहजता लंबे समय से दबे स्वर में थी, वह अब सार्वजनिक होती दिख रही है। संगठन और सरकार दोनों में मजबूत पकड़ रखने वाले विजयवर्गीय का कद उन्हें चुप मंत्री बने रहने की अनुमति नहीं देता। ऐसे में उनके बयान आने वाले दिनों में सियासी तापमान और भी बढ़ा सकते हैं।

न्यूज ब्रीफ

- दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 152 उड़ानें रद्द, कोहरे के चलते ऑपरेशन प्रभावित
- बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दर बढ़ाकर 0.75 फीसदी की, 30 साल में सबसे अधिक
- यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, एसआईआर और कफ सिरप मुद्दे पर हंगामे के आसार
- राजस्थान : बूंदी में कार पर पलटा बजरी से भरा ट्रेलर, चार की मौत, एक घायल
- बांग्लादेश : हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा, यूनुस ने दोपहर को बुलाई बैठक
- नई दिल्ली : डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट के समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी
- नई दिल्ली : आज से जनता के लिए खुलेगा सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर बना नया मेट्रो म्यूजियम
- आज से शुरू होगा यूपी विस का शीतकालीन सत्र
- लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी VB G RAM G बिल 2025 पास
- अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में लैंडिंग के दौरान बिजनेस जेट क्रैश, कई लोगों की मौत

देपालपुर जनपद पंचायत को नहीं मिला 6 माह में जनपद सीईओ

अतिरिक्त प्रभार सीईओ हफ्ते में एक बार आती है देपालपुर

निलेश चौहान : 94250-77209

देपालपुर ● दैनिक इंदौर संकेत

जनपद पंचायत देपालपुर को जिले की सबसे बड़ी जनपद कहा जाता है। लगभग 100 से अधिक ग्राम पंचायत देपालपुर विधानसभा में आती है, लेकिन यहां पर पिछले 6 माह से स्थाई जनपद सीईओ नहीं है। पूर्व में रहे जनपद सीईओ एमएल वर्मा रिटायर हो चुके हैं देपालपुर जनपद का अतिरिक्त प्रभार सांवेर की जनपद सीईओ कुसुम मंडलोई को दिया गया है। लेकिन मंडलोई देपालपुर हफ्ते में एक बार आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात किसी को अर्जेंट काम हो तो देपालपुर से सांवेर जाना पड़ता है, क्योंकि सांवेर मंत्री तुलसी सिलावट का विधानसभा क्षेत्र हैं कुसुम मंडलोई का ज्यादातर ध्यान देपालपुर की जगह सांवेर में है मंडलोई से मिलने के लिए जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। जानकारी में यह भी पता चला है कि जनपद में अलग-अलग विभाग में काम के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। जो भी काम होता है वह प्रभारी के माध्यम से कराए जाते हैं। एक तरफ तो प्रदेश सरकार अधिकारियों को 10:00 बजे उपस्थित होने के निर्देश दे चुकी है लेकिन दूसरी तरफ जनपद को सीईओ नहीं दे पा रही है। देखने में आया है कि जनपद के काम सीईओ नहीं होने से समय सीमा पर नहीं हो रहे हैं कही बार अधिकारी नहीं होने का हवाला दिया जाता है। सरकार की योजनाओं पर भी इसका असर देखने को मिला जिम्मेदार अधिकारी अपनी कुर्सी पर नहीं है तो ग्राम पंचायतों में सरकार की योजनाओं पर कैसे काम किया जाएगा।

डीएवीवी की भूमि पर अवैध कब्जों का मामला गरमाया

संवाद क्रांति की पहल लाई रंग, अवैध कब्जों के विरुद्ध शिक्षक संगठनों का भी समर्थन

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) इंदौर की भूमि-संपत्ति पर हो रहे अवैध कब्जों, दबावपूर्वक अधिग्रहण और पक्के निर्माणों के विरुद्ध संवाद क्रांति आंदोलन द्वारा महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के नाम सौंपे गए मुख्य ज्ञापन को देवता और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम), देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इकाई— दोनों का एकसाथ लिखित व औपचारिक समर्थन प्राप्त हुआ है।

दोनों शिक्षक संगठनों द्वारा जारी समर्थन पत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों की भूमि-संपत्ति का कोई भी भाग अन्य शासकीय या अर्ध-शासकीय संस्थाओं को देना तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। साथ ही पूर्व में किए गए भूमि आवंटन एवं हस्तांतरण की पुनः समीक्षा कर विश्वविद्यालय हित में निर्णय लेने की मांग की गई है। समर्थन पत्रों में यह भी उल्लेख किया गया है कि डीएवीवी के यूटीडी परिसर एवं मुख्य मार्गों से लगी भूमि पर नगर निगम, पुलिस, स्मार्ट सिटी तथा अन्य संस्थाओं से जुड़े पक्के निर्माण और अवैध कब्जे न केवल विश्वविद्यालय अधिनियम व भूमि उपयोग नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे शैक्षणिक वातावरण, सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य की विस्तार योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। देवता और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के इस समवेत समर्थन के बाद शासन-प्रशासन पर त्वरित, ठोस और निर्णायक कार्रवाई का दबाव और बढ़ गया है।

प्रमुख मांगें

- विश्वविद्यालय भूमि पर हुए सभी अवैध कब्जों एवं निर्माणों की उच्चस्तरीय जांच।
- अवैध निर्माणों को विधि अनुसार हटाकर भूमि की तत्काल वापसी।
- दोषी अधिकारियों व संस्थाओं पर प्रशासनिक व कानूनी कार्रवाई।
- विश्वविद्यालय भूमि की डिजिटल मैपिंग, सीमांकन और स्थायी सुरक्षा व्यवस्था।
- बिना कुलाधिपति व सक्षम शैक्षणिक प्राधिकरण की अनुमति किसी भी भूमि हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध।

संवाद क्रांति आंदोलन के संयोजक अधिवक्ता पंकज प्रजापति ने कहा कि यह मुद्दा केवल डीएवीवी तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की समूची उच्च शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और छात्रों के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। शिक्षक संगठनों का संयुक्त समर्थन यह दर्शाता है कि यह विषय अब एक व्यापक शैक्षणिक चिंता बन चुका है।

डीन के नोटिस के बाद तल मंजिल पर हटा ठेकेदार का कब्जा

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● एमवायएच की तल मंजिल पर गत करीब पांच वर्षों से अकाउंट विभाग का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन इसका काम खत्म ही नहीं हो रहा था। ठेकेदार ने यहां कब्जा कर अपना स्टोर रूम बना लिया था। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया। नोटिस मिलते ही अस्पताल प्रबंधन भी हरकत में आ गया और संबंधित ठेकेदार को अल्टीमेटम देते हुए तुरंत निर्माणाधीन विभाग को खाली करने के निर्देश देते हुए शीघ्र निर्माण पूर्ण करने को कहा। इसका असर यह हुआ कि ठेकेदार

खुलासे के बाद डीन ने जारी किया था नोटिस

ने अपना समान हटा लिया, जहां उसने पाइप, सेनेटरी आदि समान रखकर स्टोर की तरह इसे इस्तेमाल किया जा रहा था। गुरुवार को पूरी तरह से समान हटा लिया गया है। जानकारी मिली है कि अब दोबारा अकाउंट विभाग का कार्य गति पकड़ेगा। सबसे पहले यहां इलेक्ट्रीक का बचा हुआ कार्य शुरू किया जाएगा। इसके बाद इसका बचा हुआ रिनोवेशन का कार्य किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में एमवायएच का अकाउंट विभाग दो हिस्सों में संचालित हो रहा है। इसके चलते विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तो परेशान हो रही है, साथ अस्पताल का अन्य स्टाफ भी इससे प्रभावित हो रहा था।

शेष बचे 13 दिन... साल 2025 की यादें होगी ताजा 'दैनिक इंदौर संकेत' के साथ

इंदौर ● दैनिक इंदौर संकेत। इंदौर शहर की विरासत बनी रंगपंचमी की गेर में इस वर्ष पहली बार बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई। गेर के इतिहास में पहली बार एक महिला की भी मौत हो गई। हुड़दंगियों ने महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया। कई लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री को गेर में आने का कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा।

विलय की तैयारी | **महापौर रियायती पास और दिव्यांग छूट का बकाया**

नगर निगम पर एआईसीटीएसएल की 60 करोड़ की लेनदारी निकली

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मध्यप्रदेश में एक बार फिर रोडवेज की तर्ज पर मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा आरंभ होने जा रही है। इसके लिए इंदौर-भोपाल और उज्जैन में तैयारियों शुरू हो चुकी हैं। आने वाले मार्च माह तक इंदौर संभाग के रूट पर मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा के तहत बसों का संचालन शुरू होने की उम्मीद की जा रही है।

बसों के संचालन के लिए प्रदेश स्तरीय कंपनी का गठन किया जा रहा है, जिसमें इंदौर

नगर निगम द्वारा संचालित कंपनी अटल सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड का विलय किय जा रहा है। विलय से पहले एआईसीटीएसएल कंपनी नेटवर्थ निकाली जा रही है, जिसके तहत कंपनी को नगर निगम से 60 करोड़ रुपए की राशि लेना बकाया है।

विशेष अवसर दी गई छूट की राशि बकाया : एआईसीटीएसएल कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष महापौर को बनाया गया था, इसलिए नगर निगम द्वारा बस संचालन की व्यवस्थाओं में सहयोगी की भूमिका अदा की गई। इस दौरान विद्यार्थी, दिव्यांग और महिलाओं, वृद्धजन सहित विशेष अवसर जैसे राखी, महिला दिवस पर दी जाने वाले किराए में छूट के कारण 60 करोड़ रुपए नगर निगम पर बकाया है, जिसका भुगतान नगर निगम को एआईसीटीएसएल द्वारा किया जाना है।

कॉरिडोर हटने से सिटी बस कंपनी की आय खत्म

नगर निगम भी बसों के संचालन की जिम्मेदारी से मुक्ति चाहता है और बकाया राशि चुकाने के लिए तैयार है। एआईसीटीएसएल कंपनी संचालन के लिए नगर निगम द्वारा अपर आयुक्त स्तर के एक अधिकारी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही बीआरटीएस कॉरिडोर पर लगे विज्ञापन होर्डिंग एआईसीटीएसल के लिए मुख्य आय का साधन थे, लेकिन बीआरटीएस हटाने के बाद कंपनी की आय अब खत्म हो जाएगी।

न्यूज ब्रीफ

कारुण्य पेलिएटिव केयर के लिए आयुष डॉक्टरों की ट्रेनिंग

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● कैंसर, लकवा जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भारत सरकार, राष्ट्रीय आयुष मिशन जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इंदौर जिले में कारुण्य प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें इंदौर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गंभीर बीमारियों के मरीजों को घर पहुंच इलाज एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ताकि वह अपना जीवन आसानी से बिता सके। इस कार्य के लिए बुधवार को 55 आयुष डॉक्टर को शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में ट्रेनिंग दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजीत पाल सिंह चौहान प्राचार्य एवं विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर हंसा बारिया, जिला आयुष अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉ श्वेता वर्मा, डॉ नीरज कानूनगो, डॉ अजीत ओझा एवं डॉ अनुराग भट्ट ने पेलिएटिव केयर पर व्याख्यान दिया।

अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री सील

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● देपालपुर क्षेत्र के ग्राम जलोदिया पार में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 162/2 एवं 163/2 भूमि स्वामी आदित्य राज पिता बहादुर सिंह चावड़ा के स्वामित्व की भूमि पर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित होने की सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई थी। सूचना की पुष्टि हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी देपालपुर राकेश मोहन त्रिपाठी के निर्देशानुसार बुधवार को कार्यपालिक दण्डाधिकारी नागेन्द्र त्रिपाठी के द्वारा निरीक्षक पुलिस थाना देपालपुर रंजीत सिंह बघेल एवं अन्य पुलिस टीम व राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से मौके का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर बिना वैध अनुमति, लाइसेंस के पटाखा निर्माण संबंधी गतिविधियाँ की जा रही थीं, जो नियमों के विरुद्ध हैं।

नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों पर बड़ी कार्रवाई

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूली बसों के निरीक्षण की मुहिम प्रारंभ की गई है। इस मुहिम में आज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अमले द्वारा कनाड़िया क्षेत्र की स्कूली बसों की आकस्मिक जांच की गई। जांच में अनियमितताएं पाये जाने पर कार्रवाई की गई। बिना परमिट संचालित दो बसों को जप्त किया गया, इनसे 90 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही 7 बसों पर भी 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर वसूली की गई। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इंदौर आरटीओ द्वारा कनाड़िया रोड़ क्षेत्र के स्कूली वाहनों की सघन जांच की गई। जांच में वाहनो के परमिट ,फिटनेस ,बीमा सहित सभी दस्तावेज चेक किये गए। वाहनों का निरीक्षण भी किया गया जिसमें चेक किया गया की वाहन फिटनेस शर्तो, परमिट शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है।

सांसद लालवानी की नागरिक उड्डयन मंत्री से अहम बैठक हुई

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों को हो रही लगातार परेशानियों और बढ़ते यात्री दबाव को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने बुधवार को नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात कर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में एयरपोर्ट से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद लालवानी ने इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों को रोजमर्रा में आ रही व्यावहारिक समस्याओं को एक-एक कर मंत्री के सामने रखा। सांसद लालवानी ने बताया कि इंदौर एयरपोर्ट पर पार्किंग एरिया में लगातार भीड़ बनी रहती है। पार्किंग के बाद टर्मिनल में प्रवेश के दौरान विशेष रूप से सुबह के समय लंबी कतारें लग जाती हैं। इसके अलावा सुरक्षा जांच के दौरान भी यात्रियों को काफी देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे असुविधा बढ़ जाती है।

इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन को हरी झंडी : 19 गांवों की जमीन अधिग्रहण अधिसूचना जारी, 30 दिन में दावे-आपत्तियां, मुआवजे पर विवाद

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र तक प्रस्तावित इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन के लिए रेल मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अगले 30 दिन में रेलवे लाइन के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इस परियोजना में इंदौर जिले की तहसीलों के 19 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी।

किसान नेता हंसराज मंडलोई ने बताया कि इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना में जहां महाराष्ट्र सरकार चार गुना मुआवजा दे रही है, वहीं मध्यप्रदेश सरकार आदिवासी किसानों को केवल दोगुना मुआवजा दे रही है, जो असमानता को दर्शाता है।

महू क्षेत्र के 18 गांव होंगे प्रभावित-इंदौर जिले के महू (डॉ.अंबेडकर नगर) से शुरू होकर महाराष्ट्र के मनमाड़ तक जाने वाली इस रेलवे लाइन में महू विधानसभा क्षेत्र के 18 गांवों (खेड़ी, हस्त मुरार, चैनपुरा, कमदपुर, कुवालपुरा, अहिल्यापुरा, नांदेड़, जामली, कैलोद, बेरछा, गवली पलासिया, आशापुरा, मलेंडी, कोदरिया, बोरखेड़ी, चोरड़िया और नेवगुराड़िया) की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इन गांवों के लगभग 243 आदिवासी किसानों की 131.49 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

रेलवे ने गिनाए प्रोजेक्ट के फायदे-हंसराज मंडलोई के अनुसार रेलवे प्रशासन इस परियोजना को अत्यंत महत्वपूर्ण बता रहा है। विभाग का दावा है कि इस लाइन के बनने से इंदौर-मुंबई की दूरी करीब 250 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं तमिलनाडु से दिल्ली की दूरी लगभग 680 किलोमीटर घटेगी। महू से जम्मू-कश्मीर तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलने और गुजरात के यात्रियों को भी आवागमन में सुविधा बढ़ने का दावा किया जा रहा है।

प्रदेश में 905 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण-रेल लाइन से सबसे ज्यादा फायदा मप्र को मिलेगा। 309 किमी में 170.56 किमी का हिस्सा मप्र का है। इसमें प्रदेश की कुल 905 हेक्टेयर जमीन निजी है। मप्र में बनने वाले 18 स्टेशन में महू, कैलोद, कमदपुर, झाड़ी बरोदा, सराय तालाब, नीमगढ़, चिक्तायाबड़, ग्यासपुरखेड़ी, कोठड़ा, जरवाह, अजंदी, बघाड़ी, कुसमारी, जुलवानिया, सलीकलां, वनिहार, बवादड़ और मालवा स्टेशन है।

मुंबई जाने में 5 घंटे कम लगेंगे

इंदौर-मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट की कवायद वर्षों से चल रही है। 2023 में टोकन राशि 2 करोड़ रुपए मिली थी। मप्र के हिस्से में डीपीआर-सर्वे का काम किया गया। काम जारी रखने के लिए 2024 के बजट में एक हजार रुपए टोकन राशि दी थी। अब 18 हजार 36 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। अभी इंदौर से देवास, उज्जैन, रतलाम, थांदला, दाहोद, गोधरा, वडोदरा होते हुए मुंबई जाना पड़ता है। यह 828 किमी है। नई रेल लाइन से 188 किमी कम होंगे। 5 घंटे तक समय बचेगा।

एयरपोर्ट को फ्लाइट कैंसिल होने से करोड़ों का नुकसान होटल, पर्यटन और टैक्सी उद्योग पर भी पड़ा असर

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंडिगो की लगातार उड़ानें रद्द होने का असर सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं, बल्कि इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी की आय पर भी पड़ा है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को बीते पांच दिनों में करीब दो करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उड़ानें रद्द होने से होटल, पर्यटन और टैक्सी उद्योग के साथ-साथ एयरपोर्ट की राजस्व व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला अब भी जारी है और पिछले दो दिनों से रोज एक से दो उड़ानें निरस्त हो रही हैं। इंदौर एयरपोर्ट से रोजाना करीब 12 से 14 हजार यात्री यात्रा करते हैं, जिनमें आधे आने और आधे जाने वाले होते हैं। इंदौर से संचालित उड़ानों में इंडिगो का नेटवर्क सबसे बड़ा है और यहां की आधे से अधिक उड़ानें इसी एयरलाइन पर निर्भर हैं। 4 से 8 दिसंबर के बीच इंडिगो की कई उड़ानें प्रभावित रहीं, जिससे इन दिनों में यात्रियों की औसत संख्या 40 से 45 प्रतिशत तक घट गई।

5 दिसंबर को स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही, जब करीब 5 से 6 हजार यात्रियों को उड़ानें रद्द होने के कारण एयरपोर्ट से लौटना पड़ा। इंडिगो ने यात्रियों को टिकट की पूरी राशि वापस कर दी, लेकिन उड़ानें निरस्त होने से एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिलने वाला शुल्क लगभग शून्य हो गया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

इस तरह हुई अथॉरिटी की आय कम

इंदौर से किसी भी विमानन कंपनी का टिकट बुक कराने पर यात्रियों से यूजर डेवलपमेंट फीस (यूडीएफ), रीजनल कनेक्टिविटी चार्ज (आरसीसी) और एविएशन सिक्योरिटी फीस मिलाकर औसतन 700 रुपए से अधिक शुल्क वसूला जाता है।

यह शुल्क अलग-अलग एयरपोर्ट पर अलग-अलग होता है, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी यात्री सुविधाओं के रखरखाव और विस्तार पर खर्च करती है। सामान्य दिनों में प्रतिदिन मिलने वाले यात्री शुल्क के मुकाबले संकट के दिनों में प्रतिदिन लगभग 5 हजार से 6 हजार यात्रियों से शुल्क नहीं मिल पाया। यानी एयरपोर्ट को रोजाना लगभग 35-40 लाख रुपए तक की चपत लगी। सूत्रों की माने तो एयरपोर्ट अथारिटी को पांच दिनों का कुल नुकसान 1.75 से 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक होने का अनुमान है। एयरपोर्ट से टैक्सी का संचालन करने वाले संदीप यादव ने कहा कि उस समय लोग आए अंदर ही एयरपोर्ट में फंसे रहे। कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों को एयरपोर्ट पर लेने बुला लिया।

शासकीय लॉ कॉलेज में कट्टरता फैलाने के आरोपी रहे पूर्व प्रिंसीपल इनामुर रहमान जांच में बरी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसीपल इनामुर रहमान को तीन साल बाद कट्टरता फैलाने के आरोपों से मुक्ति मिल गई है। मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली है। एबीवीपी ने इस मामले में आंदोलन किया था। भंवरकुआं थाने पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

तत्कालीन गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। अंत में, उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र शासन के रवैए पर फटकार लगाई थी।

मप्र शासन ने यह जारी किया आदेश-मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग अवर सचिव वीरन सिंह भलावी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ABVP की तरफ इस संबंध में शिकायत की गई थी। इस पर जांच समिति बनाकर रिपोर्ट ली गई।

समिति ने शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक कट्टरता फैलाने, पक्षपाती काम करने, सामाजिक समरसता और सौहार्दता को भंग करने, और शासकीय नीतियों के खिलाफ छात्रों को गुमराह करने की बात कही थी। साथ ही, उन्होंने इसकी निंदा की थी। इस पर 9 दिसंबर 2022 को उन्हें निलंबित किया गया और विभागीय जांच बैठाई गई थी।

विभागीय जांच में यह बात आई-विभागीय जांच में साक्षियों के कथन और दस्तावेज़ों की कमी से आरोप प्रमाणित नहीं हो सके। साथ ही इस मामले में भंवरकुआं थाने में दर्ज की गई स्त्रड्ढक्र को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। इसलिए जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उनकी जांच यहीं पर समाप्त की जाती है। डॉ. रहमान 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में निलंबन अवधि 9 दिसंबर 2022 से 31 मई 2024 तक के सभी लाभ दिए जाते हैं।

यह था पूरा मामला-साल दिसंबर 2022 में सरकारी लॉ कॉलेज इंदौर में शिक्षकों पर धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप लगा। ABVP ने आरोप लगाए कि किताब सामूहिक हिंसा एवं दाण्डिक न्याय पद्धति को पढ़ाया जा रहा है जो धार्मिक सौहार्द के खिलाफ है।

किताब के लेखक डॉ. फरहत खान, प्राचार्य इनामुर्रहमान और प्रोफेसर डॉ. मिर्जा मोईज के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोप है कि किताब में बिना साक्ष्य के हिन्दू धर्म के खिलाफ झूठी टिप्पणियां की गई। मुस्लिम शिक्षकों ने जानबूझकर छात्रों को रेफर किया।

17वें युवा जनजाति आदान-प्रदान कार्यक्रम का शुभारंभ

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● केन्द्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित मेरा युवा भारत कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में 17वें युवा जनजाति आदान-प्रदान कार्यक्रम का शुभारंभ आज उत्साहपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद एवं महान जनजातीय नायक टंट्या भील के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया गया।

दीप प्रज्वलन उपरांत जिला युवा अधिकारी, मेरा युवा भारत, इंदौर पंकज गोस्वामी द्वारा कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, महापौर परिषद सदस्य बबलू शर्मा, क्षेत्रीय पार्षद नितिन शर्मा तथा उपस्थित अधिकारीगण का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। इसके बाद गोस्वामी ने कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह कार्यक्रम देश की जनजातीय युवा प्रतिभाओं के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक आदान-प्रदान को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

उन्होंने जानकारी दी कि सात दिवसीय इस आयोजन में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश एवं झारखंड के विभिन्न जनजातीय बहुल जिलों से आए युवा प्रतिभागी सहभागिता कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन ज्ञानवर्धक सत्रों का आयोजन किया जाएगा तथा सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति, परंपराओं एवं कला विधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को इंदौर शहर की ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक पहचान से परिचित कराने हेतु राजवाड़ा, लालबाग पैलेस, डॉ. भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू, सैन्य संग्रहालय तथा औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण भी कराया जाएगा।

शासकीय सेवकों के गुमशुदा जीपीएफ कटौत्रों के संबंध में विशेष शिविर प्रारंभ

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर द्वारा शासकीय सेवकों के जीपीएफ गुमशुदा कटौत्रे, निष्क्रिय जीपीएफ खाते, पार्ट वांट/फुल वांट एवं अप्रविष्ट मदों के प्रकरणों के निराकरण किये लिये कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 112 में विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रथम दिवस 15 दिसम्बर को शिविर में 14 विभागों के लगभग 85 कर्मचारियों के जीपीएफ प्रकरण प्राप्त हुये हैं। सभी विभागों से अपील की गयी है कि शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर अपने पेंडिंग प्रकरणों का निराकरण करवाएं। कलेक्टर के मार्गदर्शन में एवं वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्रीमती मोनिका कटारे के निर्देशन में सामान्य भविष्य निधि के गुमशुदा कटौत्रों तथा सामान्य भविष्य निधि जागरुकता से संबंधित शिविर का आयोजन 19 दिसम्बर किया जायेगा। इंदौर संभाग के सभी विभागों के कर्मचारियों की सूची जिनके गुमशुदा कटौत्रे हैं वह महालेखाकार ग्वालियर से आए दल द्वारा जिला कोषालय,इंदौर के माध्यम से व्हाट्सअप पर साफ्टकापी में प्रेषित कर दी गयी है।

लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और भविष्य के प्रति साझा उत्तरदायित्व के संकल्प का परिचायक है विशेष सत्र : मुख्यमंत्री

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश विधानसभा के 70 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र में विधानसभा के सभी सदस्यों का स्वागत अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध बनाने के संकल्प पर विशेष सत्र में चर्चा का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के पथ पर अग्रसर व्यवस्था के लिए यह सत्र विशेष महत्व का है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल को प्रणाम करते हुए कहा कि यह विशेष सत्र केवल औपचारिकता नहीं अपितु लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और भविष्य के प्रति साझा उत्तरदायित्व के संकल्प का परिचायक है। यह सत्र मध्यप्रदेश को सुखद, समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से गौरवशाली और आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प को दोहराने का अवसर है। विधानसभा की 70 साल की यात्रा हमारी लोकतांत्रिक यात्रा का प्रमाण है, यह सदन सत्ता का नहीं जनता के विश्वास का मंदिर रहा है।

भाजपा सरकार के 2 वर्ष सभी विधानसभाओं में सम्मेलनों के साथ मनेगा जश्न

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, महामंत्री सुधीर कोल्हे, महेश कुकरेजा व कैलाश पीपले ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा इंदौर नगर की सभी विधानसभाओं में सम्मेलनों के माध्यम से जश्न मनाया जाएगा। नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में 2 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में एतिहासिक विकास हुआ है, साथ ही जनकल्याण की इबारत लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्द4ड्डठ्ठ, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण के संकल्प को प्रदेश के लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री डॉ यादव आगे बढ़ा रहे हैं। उनके नेतृत्व में 2 वर्षों में प्रदेश में हुए एतिहासिक विकास एवं जनकल्याण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विधानसभावार सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है।

आबकारी विभाग इंदौर द्वारा दो मामलों में एक लाख 22 हजार से अधिक मूल्य की अवैध मदिरा जप्त की गई

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● कलेक्टर के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी के द्वारा दिये निर्देशानुसार इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के विरूद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी, डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र जोशी व जहांगीर खान के नेतृत्व में वृत्त- बालदा कॉलोनी एवं बाम्बे बाजार प्रभारी उप निरीक्षक मीरा सिंह के द्वारा शहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। कार्यवाही में वृत्त बालदा कालोनी में मुखबिर की सूचना पर चंदन नगर व्हाया फूटी कोटी रोड़ पर घेराबंदी कर शंका के आधार एक दोपहिया एक्टिवा वाहन को रोककर डिक्की की तलाशी ली गई। 6 बोतल और पीछे सीट पर रखे स्वेगी बैग में 18 बोतल, एक कपड़े के झोले में 12 केन बीयर व 6 बोतल में अलग-अलग ब्रांड की विदेशी की शराब जप्त की।

पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैंस के राजदार बिल्डर राजेश शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैंस के राजदार और त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शर्मा के खिलाफ ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध विंग) में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। वहीं अब हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए सभी पक्षों को नोटिस भेजा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी 2026 को होगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को स्वीकार किया है। इसके अलावा राजेश शर्मा, उनकी फर्म ट्राइडेंट मल्टी वेंचर्स, और उनके सहयोगी राजेश तिवारी तथा दीपक तुलसानी को भी नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्देशित किया है कि वे अगली सुनवाई तक कोर्ट में अपना जवाब और हलफनामा पेश करें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। 28 जुलाई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह मामला निजी सिविल विवाद से जुड़ा है। एफआईआर गलत इरादे से दर्ज की गई थी, ताकि निजी लाभ हासिल किया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए एफआईआर रद्द की जा रही है। इसके बाद, किसान और ईओडब्ल्यू ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। साथ ही, सभी पक्षों को जवाब व हलफनामा कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। राजेश शर्मा ने अपनी फर्म ट्राइडेंट मल्टीवेंचर्स के कर्मचारियों की मदद से फर्जीवाड़ा किया था। उन्होंने रातीबड़ के किसान चिंता सिंह मारण की 12.46 एकड़ कृषि जमीन खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने किसान का खाता ICICI बैंक की नेहरू नगर शाखा में खुलवाया था। वहीं, मोबाइल नंबर और मेल आईडी राजेश तिवारी का डाल दिया था। 12 जून 2023 को उन्होंने रजिस्ट्रार के पास आवेदन करके 2 करोड़ 86 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराई थी। वहीं किसान को केवल 81 लाख 13 हजार रुपए दिए गए थे। बाकी पैसा उन्होंने अपने पास रख लिया था। साथ ही, 66 लाख के चेक को स्टॉप पेमेंट कर वापस लिया था। वहीं, 1 करोड़ 36 लाख रुपए किसान के खाते से राजेश तिवारी के खातों में ट्रांसफर कर दिए थे। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने राजेश शर्मा, दीपक तुलसानी और राजेश तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया था।

ये तीन खिलाड़ी पूरे खेल में शामिल

राजेश शर्मा : इस पूरे मामले की साजिश रचने वाला शख्स है। अपनी पत्नी राधिका शर्मा के साथ मिलकर मेसर्स ट्राइडेंट मल्टीवेंचर्स नाम से फर्म चलाई। इसी फर्म के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। दस्तावेज तैयार करवाए, बैंक खाता खुलवाया और ट्रांजेक्शन को कंट्रोल किया था।

दीपक तुलसानी: ट्राइडेंट का हस्ताक्षरकर्ता था, रजिस्ट्री में उसका नाम भी खरीदार के रूप में आया, लेकिन हकीकत में वह बस नाम मात्र का चेहरा था। उसका असली रोल सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित था।

राजेश तिवारी: तकनीकी मदद करने वाला साथी, जो फर्जी खाता चलाता रहा। उसी के मोबाइल नंबर और ईमेल से खाता खोला गया और सारे ऑनलाइन लेन-देन उसी ने किए थे। इसी खाते से रकम निकाल कर अपने IDFC खाते में डाली थी।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
इंदौर, शुक्रवार 19 दिसंबर 2025

न्यूज ब्रीफ

भाजपा जिला ग्रामीण की टीम से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी- सिलावट

इंदौर ● मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अपने निज निवास में भाजपा जिला इन्दौर ग्रामीण के नवनियुक्त सभी भाजपा पदाधिकारियों का सम्मान किया। इस अवसर पर मंत्री सिलावट ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बडी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रवणसिंह चावडा ने जिले की नवनियुक्त पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा कर संगठन को नई ऊर्जा दी है। इस घोषणा में कई महत्वपूर्ण पदों पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिससे सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, इस ऊर्जा को हमें पार्टी के काम में लगाना है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी और म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवजी के नेतृत्व में हमें भाजपा और संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी ऊर्जा से काम करना होगा।

मां शाकम्भरी का 26 वां महोत्सव 3 जनवरी को, तांडव आरती भी होगी

इंदौर ● साग-सब्जी, फल-फूल उपलब्ध कराने वाली मां शाकम्भरी देवी सकराय माताजी का 26 वां महोत्सव इस बार शनिवार, 3 जनवरी को बायपास स्थित सम्पत पैलेस गार्डन पर मनाया जाएगा। महोत्सव का यह 26 वां वर्ष होगा। महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान प्रसिद्ध परंपरागत तांडव आरती भी होगी। महोत्सव में सुबह से रात तक विभिन्न आयोजन होंगे। मालवांचल के विभिन्न शहरों के अनेक श्रद्धालु भी इस महोत्सव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।

8 माह से चल रहा काम, रहवासी बोले धूल के कारण एलर्जी के मरीज हो गए

चौड़ीकरण की धीमी रफ्तार परेशानियों का अंबार

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ●सिंहस्थ 2028 के चलते शहर के आंतरिक मार्गों के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसके तहत कोयला फाटक से निजातपुरा होते हुए कंठाल रोड तक चौड़ा किया जा रहा है लेकिन इसकी धीमी रफ्तार ने रहवासियों के लिए परेशानियों का अंबार लगा दिया है। एक ओर जहां कारोबारियों का व्यापार ठप हो गया है, वहीं धूल-मिट्टी, चौक नालियां, सड़क पर फैलता गंदा पानी और उससे पनपत मच्छरों ने रहवासियों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

म हाकाल महालोक बनने के बाद पर्यटन को पंख लग गए हैं। देशभर से रिकॉर्डतोड़ श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा आगामी सिंहस्थ महापर्व में भी 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है जिसके लिए यह चौड़ीकरण किया जा रहा है। 1.2 किमी के लंबे इस मार्ग को 11 मीटर (करीब 36 फीट) चौड़ा किया जाना है जिसके दोनों ओर 1.2-1.2 मीटर के फुटपाथ बनाए जाएंगे। इसे बनाने का जिम्मा भोपाल की बिलीफ बिल्डकान के पास है जिसे सिंहस्थ के पहले पूरा करना है। इसकी लागत करीब 14.5 करोड़ रुपए है।

इन परेशानियों से मुश्किलें

- कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक रोड चौड़ीकरण का काम शुरू हुए करीब 8 माह हो चुके हैं लेकिन इसकी गति बेहद धीमी है जिससे कारोबार ठप हो गया है।
- दिनभर धूल और मिट्टी उडने से लोगों को सांस की परेशानी होने लगी है।
- पानी की पाइप लाइन भी कई जगह से फूट रही है जिसके कारण पानी व्यर्थ बहता है और कीचड़ होता है।
- जगह-जगह मलबा पड़ा है जिससे नाले-नालियां चौक हो गई हैं जिससे गंदा पानी दुकानों और घरों के आगे भर जाता।
- गंदे पानी के कारण मच्छरों की भी भरमार हो रही है जिससे बाहर बैठना भी मुश्किल।
- नल कनेक्शन नहीं होने से सुबह पानी ऐसे ही बहता रहा है जिससे कीचड़ होता है और वाहन चालक फिसलते हैं।

टुकड़ों-टुकड़ों में काम चलने से परेशानी

8 महीने से यह रोड इसी हालत में है। पब्लिक के साथ हम भी परेशान हैं। निर्माण कार्य के चलते काम नहीं कर पा रहे, ना ही दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं। दो दिन पहले दुकान के सामने वाले हिस्से को खोद दिया गया तब से इसका मलबा ऐसे ही पड़ा है। इसके उठाने तक नहीं गया। टुकड़ों-टुकड़ों में काम चलने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रही है।
- **नसीम खान**, कर्मचारी, सतनाम ऑटो पार्ट्स

धूल-मिट्टी के कारण एलर्जी के मरीज हो गए हैं

इस काम को देखते-देखते कई महीने बीत गए हैं। घर व दुकानों को चौड़ीकरण के लिए तोड़ा गया, वह ठीक है लेकिन इस काम को जल्द खत्म करना चाहिए। मैं तो धूल-मिट्टी उडने के कारण सर्दी-खांसी और एलर्जी का मरीज हो गया हूं। नालियां चौक हैं, ऐसे में गंदा पानी दुकान के आगे भर जाता है जिससे मच्छर हो रहे हैं। बार-बार जेसीबी पाइप लाइन फोड़ जाती है जिसे चार बार रिपेयर करवाना चुका हूं।
- **रामू साहू**, संचालक, जय महाकाल किराना और आटाचक्की

आईआईएम में जल्द ही जेन जी पोस्ट ऑफिस शुरू करेगा डाक विभाग..

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● भारतीय परिवेश में डाक विभाग की जड़ें बहुत गहरी हैं। आम नागरिकों का विश्वास शुरू से ही डाकघर और डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं पर रहा है। बदलते दौर में आधुनिकता से कदमताल करता डाक विभाग इंदौर के आईआईएम संस्थान में जल्दी ही जेन-जी पोस्ट ऑफिस शुरू करने जा रहा है। यह बात पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर परिक्षेत्र प्रीति अग्रवाल ने कही। वे गुरुवार को इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित तीन दिवसीय डाक विभाग से संबंधित शिविर के शुभारंभ अवसर पर बोल रही थी। उन्होंने बताया कि जेन-जी पोस्ट ऑफिस का उद्देश्य युवाओं को डाक विभाग की बचत, बैंकिंग और बीमा योजनाओं से जोडना है। इस पोस्ट ऑफिस को एक कैफेटेरिया का रूप दिया गया है जिसमें डिजिटल माध्यम से युवा वर्ग सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। सुश्री अग्रवाल ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर भी विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि मीडियाकर्मियों के लिए हमारा विभाग हरसंभव मदद करने को तैयार है।

इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक कर्दम ने प्रेस

क्लब में आधार अपडेशन और डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए शिविर आयोजित करने पर पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल और डाक विभाग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर का मीडियाकर्मियों को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।

इस मौके पर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अरविंद तिवारी, डाक विभाग के रीजनल मैनेजर अमित अग्रवाल, सहायक निदेशक दिनेश डोंगरे, राजेन्द्र व्यास, वरिष्ठ पोस्ट मास्टर श्रीनिवास जोशी, बीपीसी मैनेजर अशोक जखोड़े सहित डाक विभाग की टीम मौजूद थी।

अतिथियों का स्वागत उपाध्यक्ष संजय त्रिपाठी, प्रियंका पांडेय, सचिव अभिषेक चेंडके, कार्यकारिणी सदस्य मनीष मक्खर, अभय तिवारी, प्रमोद दीक्षित, श्याम कामले, पूनम शर्मा, विजय भट्ट ने किया। कार्यक्रम का संचालन महासचिव प्रदीप जोशी ने किया आभार कोषाध्यक्ष मुकेश तिवारी ने माना।

आधार कार्ड में सुधार के लिए उमड़ी भीड़ - शिविर का सबसे बड़ा लाभ मीडियाकर्मियों एवं उनके परिजनों को आधार कार्ड सुधार के रूप में प्राप्त हुआ। आधार अपडेशन काउंटर पर पूरे दिन खासी भीड़ लगी रही। हालांकि आधार कार्ड अपडेशन का कार्य शुक्रवार और शनिवार को भी किया जाएगा। डाक विभाग की बीमा पॉलिसी, सुकन्या बचत योजना सहित अन्य बचत योजनाओं के प्रति भी मीडियाकर्मियों भी उत्साह देखा गया।

माता के भजन...

इंदौर ● मंदिर समिति के अध्यक्ष पंडित सुरेश शर्मा ने बताया की संगीतकार प्रकाश गौड के संगीत निर्देशन में भजन गायक बाबू राजोरिया उर्मिला राजोरिया एवं राजेश दीवान ने एक से बढ़कर एक माता की भेंट सुनाकर भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया।

कपड़ा व्यापारियों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो और आरोपी क्राइम ब्रांच की कार्यवाही में गिरफ्तार

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर कमिश्नरेट क्षेत्र में धोखाधड़ी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही के निर्देश पुलिस आयुक्त, नगरीय इंदौर द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित प्रकरणों में निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आवेदक मुकेश (निवासी इंदौर) द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत के आधार पर जांच की गई। शिकायत में बताया गया कि जुलाई-अगस्त 2024 से 26 मार्च 2025 के बीच आरोपियों ने स्वयं को विश्वसनीय ब्रोकर बताकर इंदौर के रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों से संपर्क किया। आरोपियों ने राज्य के बाहर स्थित विभिन्न फर्मों से बड़े ऑर्डर दिलाने, 30-45 दिनों में भुगतान सुनिश्चित कराने तथा पार्टियों को भरोसेमंद बताकर व्यापारियों का विश्वास अर्जित किया।

जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों द्वारा गुड बॉय, दीप दर्शन ट्रेडर्स, अद्विक क्रिएशन, बालाजी अपैरल्स, हेमन्त गार्मेंट्स, नाइस मेन गार्मेंट्स, अरिहंत कलेक्शन, रितिक फैशन, सॉफ्टवेयर, वंदना क्रिएशन, आर.आर. रेडीमेड, शिवकृपा रेडीमेड, कनिष्का स्टिचिंग सेंटर, किड्स पावर, मेपल ट्राउजर, स्टार बाय सहित अन्य रेडीमेड व्यापारियों से लगभग 1,69,96,876/- मूल्य का कपड़ा माल ड्रूक ट्रेडिंग, साई इम्पेक्स, हर्षा ट्रेडर्स, रॉयल क्रिएशन, टेक्सटाइल, राशि कलेक्शन, ओवरसीज लिमिटेड, शिवशक्ति इंडस्ट्रीज, जुबिया टेक्सटाइल, फेब्रिक वर्ल्ड, खुशबू एंटरप्राइजेज आदि बाहरी फर्मों को भिजवाया गया।

सरवटे बस स्टैंड के अंदर नीचे का सुन्दर स्वरुप बिगाड़ा पत्तरे की अवैध रूप से पीले रंग की गुमटी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव शहर कांग्रेस के पूर्व महामंत्री नीतीश भारद्वाज ने बताया है कि सरवटे बस स्टैंड के अंदर नीचे का सुन्दर स्वरुप बिगाड़ते हुए अवैध रुप से पीले रंग की लोहे की पत्तरे की अवैध गुमटी का निर्माण कर कैंटीन खोलने की तैयारी की जा रही है। जब ऊपर की दूसरी मंजिल पर हाल में कैंटीन का टेंडर हुआ था ऊपर का कैंटीन हाल बंद कर नीचे नियमों को ताक में रखते हुए अवैध रुप से अवैध गुमटी रखने की अनुमति क्या नगर निगम ने दी हैं। नगर निगम ने किस नियम के तहत गुमटी रखने की अनुमति एवं टैंडर क्या दिया हैं जब पुराना बस

स्टैंड तोड़ा गया था और नया बस स्टैंड बनाए गया था तब के महापौर विधायक निगम आयुक्त ने घोषणा की थी कि नए बस स्टैंड के अंदर नीचे कोई दुकानें नहीं निकाली जाएगी नहीं कैंटीन खुली जाएगी नहीं कोई गुमटी रखी जाएगी उसके बावजूद भी अवैध रुप से गुमटी का निर्माण कर दिया गया हैं।

शहर के बिजली कार्मिकों ने सीखीं सुरक्षा, सावधानियां

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ●पश्चिम शहर संभाग का विद्युत सुरक्षा जागरूकता शिविर टिगरिया बादशाह, सुपर कोरिडोर इन्दौर स्थित गार्डन में आयोजित हुआ विधुत सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर में शहर अधीक्षण अभियंता डीके गाठे , कार्यपालन अभियंता सुनील सिंह, कार्यपालन यंत्री , गौतम साहू विधुत सुरक्षा विभाग अधिकारी ने मार्गदर्शक दिया। अभियंता अरूण सिंह,राम देशमुख, भास्कर घोष, नर्सिंग स्टाफ से श्रीमती शैला कामठे द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग , विद्युत दुर्घटना जोखिम एवं सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण, विद्युत सुरक्षा नियम एवं मानक, दुर्घटना सहायता एवं प्राथमिक उपचार, ग्रिड की कार्य प्रणाली एवं लाइनों को डिस्चार्ज करने की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
आपकी बात, इंदौर संकेत के साथ

डिजिटल रूप से लाखों पाठकों के साथ अपना नियमित संपर्क बनाते हुए दैनिक इंदौर संकेत अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप भी अपने संस्थान, उत्पाद, संस्था का प्रचार-प्रसार दैनिक इंदौर संकेत के माध्यम से सकते हैं। इसके तहत आप चाहे प्रापर्टी व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई बधाई संदेश देना है या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो या कोई अन्य कैटेगरी में विज्ञापन देना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दैनिक इंदौर संकेत संवेदनापूर्ण संदेशों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए इस समाचार पत्र में शोक संदेश नि:शुल्क प्रकाशित किए जाएंगे।

कार्यालय का पता
5/6, राज मोहल्ला, महेश नगर,
गुरुद्वारे के सामने, इंदौर
संपर्क: 94250-64357, 94245-83000

जल संरक्षण या जल उपेक्षा? निपानिया तालाब बना सिस्टम की नाकामी का प्रतीक

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● स्वच्छता और जल संरक्षण के दावों के बीच इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 36 में स्थित, इस्कॉन मंदिर से सटा निपानिया तालाब आज उपेक्षा, लापरवाही और सरकारी संवेदनहीनता की मूक गवाही दे रहा है। कभी इस तालाब के साफ-सफाई और जीर्णोद्धार के लिए बजट स्वीकृत हुआ था, तो दो वर्ष पूर्व सघन वृक्षारोपण अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर प्रचार भी किया गया। पर जमीनी सच्चाई यह है कि आज यह तालाब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। तालाब के चारों ओर जंगली झाड़ियाँ, गंदगी और बदबू फैली हुई है। वृक्षारोपण के नाम पर लगाए गए पौधों में से एक भी पौधा जीवित नहीं बचा। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि बायपास पर स्थित होटल और मैरिज गार्डनों का प्रदूषित जल खुलेआम इस तालाब में प्रवाहित हो रहा है, जिससे इसका जल पूरी तरह दूषित हो चुका है।

निपानिया तालाब, जो शहर के पूर्वी क्षेत्र का एक प्रमुख जलस्रोत और संभावित वेटलैंड हो सकता था, आज अनधिकृत कब्जों के घेरे में सिमटता जा रहा है। बावजूद इसके,

नगर निगम, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग अनभिज्ञ होने का अभिनय करते नजर आ रहे हैं।स्थानीय नागरिकों और ग्रामीणों ने बार-बार ज्ञापन सौंपकर तालाब के समग्र विकास, सौंदर्यीकरण, चारों ओर छठ घाट, पाथवे, बगीचे और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था की मांग की, ताकि यह तालाब जनउपयोगी और पर्यावरण-अनुकूल बन सके। मगर हर बार आश्वासन मिले, पर काम शून्य रहा। समाज सेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार के के झा ने कहा कि दो वर्ष पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 2 करोड़ रुपए निपानिया तालाब के जल संरक्षण हेतु पारित किये गए थे पर इतने बड़े रकम को कहाँ खर्च किया गया, वो तालाब के आसपास कहीं दिख नहीं रहा है।

म.प्र. जन अभियान परिषद के नवांकुर और परामर्शदाताओं की जिला समीक्षा बैठक संपन्न

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● होलकर साइंस कॉलेज, इंदौर में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद इंदौर जिले की नवांकुर संस्थाओं और परामर्शदाताओं की जिला समीक्षा बैठक का आयोजन मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक महोदय के मुख्य आतिथ्य, परिषद के शासी निकाय सदस्य विनोद मोहने, होलकर साइंस कॉलेज की प्राचार्य डॉ. अनामिका जैन के विशिष्ट आथित्य में की गई। इस दौरान परिषद के संभाग समन्वयक श्री अमित शाह, जिला समन्वयक श्रीमती ऋतुजा पहाडे, समस्त विकासखंड के विकासखंड समन्वयक, जिले के समस्त नवांकुर संस्था पदाधिकारी, परामर्शदाता उपस्थित रहे। बैठक का शुभारंभ सरस्वती माता की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ हुआ। बैठक के दौरान परिषद के कार्यपालक निदेशक महोदय द्वारा नवांकुर संस्थाओं और परामर्शदाताओं द्वारा उनके क्षेत्र में किया जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई। नवांकुर संस्था प्रतिनिधियों ने उनको आवंटित सेक्टर में की जा रही गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता पाठ्यक्रम अंतर्गत कार्यरत मेंटर्स के द्वारा पाठ्यक्रम में संचालित कक्षा के संचालन और विद्यार्थियों के प्रयोगशाला ग्राम में की जा रही गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की।

सम्पादकीय

ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी की नई व्यवस्था कितनी सहायक साबित होगी?

कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़ कर 'बीवी- जी राम जी' के तहत होने वाले कुल खर्च का साठ फीसद केंद्र सरकार वहन करेगी और चालीस फीसद राज्य सरकारें उठाएंगी। देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर आबादी के लिए रोजी-रोटी का इंतजाम एक बड़ी चुनौती रही है। लंबे समय तक इस समस्या के बने रहने का नतीजा यह हुआ कि विकास एक तरह से विभाजित रहा और एक बड़ा तबका मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिशों से भी वंचित रहा। मगर जब से गारंटी के रूप में ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराने की पहल हुई है, उसके बाद से एक बड़ा फर्क दर्ज किया गया। करीब बीस वर्ष पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा लागू हुआ, तो उसके तहत वर्ष में सौ दिन काम की व्यवस्था से गांव-देहात में रहने वाले परिवारों के सशक्तीकरण में उल्लेखनीय मदद मिली। मनरेगा की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई बार इसे दुनिया भर में एक सीखने लायक कार्यक्रम के तौर पर भी देखा गया। अब केंद्र सरकार ने मनरेगा का रूप बदल कर उसका नाम 'विकसित भारत-रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी 'वीबी- जी राम जी' रखा है और उसमें अब कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। इससे संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। गौरतलब है कि नई प्रस्तावित व्यवस्था मनरेगा का ही नया स्वरूप होगी, जिसमें ग्रामीण परिवार को सौ दिन के बजाय एक सौ पच्चीस दिनों के रोजगार की गारंटी की बात की गई है। इसके अलावा, खर्च वहन करने, पारिश्रमिक भुगतान और खेती के दिनों के संदर्भ में नए प्रावधानों की वजह से इस योजना के किसानों और मजदूरों, दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने की उम्मीद की जा रही है। मनरेगा के तहत जिन लोगों को काम मिलता है, उनकी मजदूरी का लगभग पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती रही है, जबकि सामान आदि का खर्च एक निश्चित अनुपात में राज्य सरकारें उठाती हैं। अब कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़ कर 'बीवी- जी राम जी' के तहत होने वाले कुल खर्च का साठ फीसद केंद्र सरकार वहन करेगी और चालीस फीसद राज्य सरकारें उठाएंगी। इस योजना के अंतर्गत खेतों में बुआई और कटाई के मौसम में साठ दिनों के दौरान मजदूरों को काम नहीं मिल सकेगा, ताकि खेती-किसानी के काम के लिए मजदूरों की कमी न हो। इसके अलावा, इस काम में भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए मजदूरी के भुगतान में बायोमेट्रिक और अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाएगी।

गोवा अग्निकांड जैसी घटनाएं भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों, प्रशासनिक लापरवाही, लाइसेंसों की अवैध खरीद- फरोख्त और निरीक्षण एजेंसियों की मिलीभगत का दुष्परिणाम?

भारत तेज़ी से शहरी विकास,बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनसंख्या की बढ़ती आर्थिक भागीदारी के दौर से गुजर रहा है,जिसके परिणामस्वरूप देश के लगभग 780 जिलों में विशाल संख्या में मॉल,मल्टी-स्टोरी बिल्डिंगें, होटल, रेस्टोरेंट,नाइट क्लब, सिनेमाहॉल,सुपर बाजार,कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज और मनोरंजन केंद्रों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इन स्थानों पर प्रतिदिन हजारों-लाखों नागरिक आते हैं, जो आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन इसी विकास की यात्रा के भीतर एक गंभीर प्रश्न भी मौजूद है,भ्रष्टाचार,गैर-जवाबदेही, फायर-सेफ्टी की अनदेखी और प्रशासनिक निरीक्षण की कमी, जो कई बार बड़े हादसों का कारण बन जाती है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में लगी भयंकर आग, जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हुई, इस समस्या का चरम उदाहरण है।इस हादसे ने यह उजागर कर दिया कि देश के अनेक जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान सक्रिय हैं, जिनके पास न तो वैध फायर-सेफ्टी प्रमाणपत्र हैं, न बिल्डिंग बायलॉज की स्वीकृति, न ही नगर परिषद/महानगर पालिका/राज्य सरकार द्वारा जारी आवश्यक लाइसेंस। यह स्थिति केवल प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम नहीं है,बल्कि भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों, लाइसेंसों की अवैध खरीद-फरोख्त,और निरीक्षण एजेंसियों की मिलीभगत का दुष्परिणाम है। जिस प्रकार गोवा के नाइट क्लब को बिना उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलने दिया गया,उसी प्रकार देश के विविध हिस्सों में भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन आम हो चुका है, जिसे रोकने के लिए अब कलेक्टर-स्तर पर स्वत: संज्ञान आधारित निरीक्षण व्यवस्था लागू करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है।

साथियों बात अगर हम भीड़भाड़ वाले प्रतिष्ठानों में सुरक्षा संकट और भ्रष्टाचार की संरचनात्मक भूमिका को समझने की करें तो, भारत में एक ओर जहांआधुनिक मॉल, कैफे, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन केंद्र शहरों की पहचान बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा स्थिति भयावह रूप से कमजोर पाई जाती है।कई जिलों में यह पाया गया है कि(1) फायर-सेफ्टी ऑडिट वर्षों तक नहीं हुए,(2) आपातकालीन निकास अवरुद्ध हैं,(3)फायर-अलार्म और स्प्रिंकलर कार्यरत नहीं (4) बिल्डिंग बायलॉज का पालन न्यूनतम,(5)ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग,(6)अवैध निर्माण और अवैध विस्तार,(7) बिना अनुमति नाइट क्लब, बार, बेसमेंट रेस्टोरेंट और कोचिंग केंद्र संचालन,(8)और सबसे चिंताजनक-भ्रष्टाचार के चलते फर्जी लाइसेंस जारी करना।भारतीय नगर प्रशासन या स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार नई बात नहीं है, लेकिन जब यह भ्रष्टाचार नागरिक जीवन के मूलभूत अधिकार, सुरक्षित वातावरण को खतरे में डाल दे, तब यह केवल रिश्वत का मसला नहीं रहता,बल्कि नागरिकों की हत्या नरसंहार जैसी परिस्थितियों को जन्म देने वाली संरचनात्मक विफलता बन जाता है।गोवा की

घटना हो या दिल्ली के मुंडका फायर हादसा, मुंबई का कमला मिल फायर, सूरत का कोचिंग सेंटर मामला,हर घटना के पीछे एक सामान्य कारण दिखाई देता है:भ्रष्टाचार के बदले मिले फर्जी प्रमाणपत्र और नियमों के क्रियान्वयन में गहरी प्रशासनिक उदासीनता?भारत में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, फायर सेवा अधिनियम, नगर बायलॉज और राष्ट्रीय भवन संहिता जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन जब इन कानूनों के पालन की जिम्मेदारी संभालने वाला निचला -मध्यम प्रशासन ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए, तो सुरक्षा व्यवस्थाएँ केवल कागज़ी बनकर रह जाती हैं। इसलिए यह मॉडल अब अप्रभावी माना जा रहा है और आवश्यक है कि निरीक्षण का अधिकार सीधे जिलाधिकारी /कलेक्टर के हाथों में आए, जो जिले का सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी होता है और भ्रष्टाचार- रोधी शक्तियाँ भी रखता है। अगर हम कलेक्टर द्वारा स्वत: संज्ञान आधारित आकस्मिक निरीक्षण की अपरिहार्यता को समझने की करें तो,प्रत्येक जिले में कलेक्टर स्वयं आकस्मिक निरीक्षण करें,वह वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक अत्यंत व्यवहार्य, प्रभावी और नागरिक-हितकारी समाधान है।इसका कारण स्पष्ट है (1) कलेक्टर भ्रष्टाचार-रोधी शक्तियों से लैस होता है।(2) स्थानीय निकाय, नगर परिषद या निगम पर होने वाले राजनीतिक दबाव का प्रभाव कलेक्टर पर कम पड़ता है। (3) स्वत: संज्ञान लेने की शक्ति के कारण कलेक्टर किसी भी संस्था पर तात्कालिक जांच और कार्रवाई कर सकता है। (4) आकस्मिक निरीक्षण भ्रष्टाचार की रीढ़ तोड़ने वाला सबसे प्रभावी उपाय है।(5) कलेक्टर की प्रत्यक्ष निगरानी से स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही स्वत: बढ़ जाती है।देश में अक्सर देखा गया है कि फायर सेवा विभाग, नगर निगम या लाइसेंसिंग अधिकारी भ्रष्टाचार के कारण बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नियमों के उल्लंघन के बावजूद 'क्लीन चिट' दे देते हैं। ऐसे में यदि कलेक्टर हर जिले में-मॉल, होटल,नाइट क्लब,बड़े रेस्टोरेंट मल्टीप्लेक्स सुपर बाजार,स्कूल/कॉलेज,कोचिंग सेंटर,और उच्च भीड़- घनत्व वाली इमारतों का स्वत: संज्ञान लेकर निरीक्षण करें, तो नागरिक सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ सकता है कलेक्टर- स्तरीय निरीक्षण से यह भी सुनिश्चित होगा कि फर्जी सर्टिफिकेट रखने वाले प्रतिष्ठानों की तुरंत पहचान की जाए और उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो। गोवा हादसा इसी बात का प्रमाण है कि यदि जिला प्रशासन सक्रिय रूप से ऐसे प्रतिष्ठानों पर समय- समय पर निगरानी करता, तो शायद 25 निर्दोष नागरिकों की जान बच सकती थी। हम भीड़-उपस्थितियों वाले संस्थानों पर अनिवार्य नियमित निरीक्षण: एक नई राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता इसको समझने की करें तो, प्रत्येक जिले में सभी ऐसे संस्थानों पर जहाँ बड़ी संख्या में आम जनता एकत्रित होती है, नियमित निरीक्षण व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। यह निरीक्षण त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक न होकर व्यवसाय के प्रकार, भीड़ की मात्रा, जोखिम स्तर और भवन संरचना के आधार पर होना चाहिए।उदाहरण के लिए,नाइट क्लब, बार, बेसमेंट रेस्टोरेंट मासिक निरीक्षण,मल्टीप्लेक्स, मॉल, भीड़भाड़ बाजार हर तीन माह में निरीक्षण,स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सत्रारंभ से पहले अनिवार्य निरीक्षण होटल और गेस्टहाउस प्रत्येक छह माह में निरीक्षण इन निरीक्षणों में निम्न बिंदुओं की सुनिश्चितता आवश्यक है (1) फायर सेफ्टी उपकरणों की कार्यशीलता (2) आपातकालीन निकास मार्ग (3)भीड़ नियंत्रक तकनीक (4) इलेक्ट्रिकल वायरिंग की सुरक्षा(5) एलपीजी/गैस सुरक्षा(6) बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन (7) सुरक्षा कर्मियों की प्रशिक्षित टीम(8) सीसीटीवी और नियंत्रण प्रणाली,भारत में कई हादसों की मुख्य वजह यह रही है कि ऐसे निरीक्षण या तो कभी हुए ही नहीं, या निरीक्षण रिपोर्ट भ्रष्टाचार के कारण कागज़ में पास दिखाई गई। इसलिए, कलेक्टर-स्तरीय निगरानी के साथ-साथ डिजिटल पब्लिक इन्स्पेक्शन रजिस्टर की व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए ताकि जनता खुद जान सके कि उनके जिले के प्रतिष्ठानों ने कौन-कौन से सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं। सुरक्षा नियमों के पालन की सार्वजनिक घोषणा इंडिया सेफ्टी चार्ट का अनिवार्य प्रदर्शन इसको समझने की करें तो,विश्व के कई देशों में, जैसे सिंगापुर, जापान, कनाडा और जर्मनी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एक पब्लिक सेफ्टी चार्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है। भारत में भी ऐसा मॉडल अपनाने का समय आ चुका है।इस भारत सुरक्षा चार्ट / इंडिया सेफ्टी कम्पलायंस चार्ट में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए- (1)अंतिम फायर सेफ्टी प्रमाणन की तिथि (2) बिल्डिंग बायलॉज अनुपालन स्तर (3) इमरजेंसी निकास योजना(4) अग्निशमन उपकरणों की क्षमता व स्थिति (5) अधिनियमों के अंतर्गत उठाए गए सुरक्षा कदम (6) स्वच्छता और विद्युत सुरक्षा जांच की तिथि (7) कलेक्टर अथवा अधिकृत अधिकारी का डिजिटल सत्यापन, इस चार्ट को रेस्टोरेंट, मॉल, होटल, थिएटर, संस्थानों व नाइट क्लब के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए, ताकि नागरिक स्वयं जान सकें कि जिस स्थान पर वे जा रहे हैं, वह सुरक्षित है या नहीं। यदि कोई प्रतिष्ठान इस चार्ट को प्रदर्शित नहीं करता, तो उसे स्वत: जोखिम-श्रेणी में रखा जाए और कलेक्टर कार्रवाई करें। हम लाइसेंस उल्लंघन, अवैध संचालन और गैर-अनुपालन पर कठोर कार्रवाई इसको समझने की करें तो,बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर तत्काल लाइसेंस रद्द किया जाए,एक व्यावहारिक और नागरिक- अधिकार आधारित मांग है। भारत में कई बार देखा गया है कि अवैध ढंग से संचालित प्रतिष्ठान- (1)राजनीतिक संरक्षण, (2) पुलिस/नगर निकाय भ्रष्टाचार, (3) या सिस्टम की ढिलाई, के कारण वर्षों तक चलाते रहते हैं। जबकि वे हजारों लोगों की जान खतरे में डालते हैं।यदि कलेक्टर स्तर पर निम्न नीतियाँ लागू की जाएँ-(1)पहली बार में 10 लाख तक का जुर्माना+15 दिन का निलंबन (2) दूसरी बार में लाइसेंस का स्थायी रद्दीकरण (3)तीसरी बार में आपराधिक मुकदमा (आईपीसी 304, 336, 337, 338 के तहत) तो ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा।नियमों का उल्लंघन केवल प्रशासनिक गलती नहीं है,यह सीधे-सीधे नागरिक जीवन को खतरे में डालने की साजिश है, जो गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। कलेक्टर यदि इसपर कड़ाई से कार्रवाई करें, तो भ्रष्टाचार की श्रृंखला स्वत: टूट जाएगी। भ्रष्टाचार इन सभी हादसों की जड़ क़ा कारण है इसको समझने की करें तो, जनता जानती है,ऐसी लापरवाही बिना नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार की मिलीभगत के संभव ही नहीं। यह एक संरचनात्मक समस्या है, जिसमें शामिल होते हैं-निरीक्षण अधिकारी, लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी, स्थानीय निकाय कर्मचारी,राजनीतिक दबाव,भ्रष्ट ठेकेदार और बिल्डर और कभी-कभी पुलिस जब भ्रष्टाचार नियमों का स्थान ले लेता है तो,(1) आग सुरक्षा कागजों में पास हो जाती है,(2) लाइसेंस रिश्वत के आधार पर जारी हो जाता है,(3)निरीक्षण रिपोर्ट फर्जी तैयार हो जाती है,(4)अवैध निर्माण को अनदेखा कर दिया जाता है,(5) और किसी दुर्घटना से पहले कोई कार्रवाई नहीं होती।गोवा का नाइट क्लब हादसा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ,(1) अवैध विद्युत कनेक्शन,(2)फर्जी लाइसेंस,(3)ओवर-कैपेसिटी भीड़,(4)आपातकालीन निकास बंद,और (5)फायर सिस्टम गैर- कार्यशील,जैसी खामियाँ बाद में सामने आईं। यह सब केवल एक ही चीज़ की ओर इशारा करता है -भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता। इसलिए भारत को अब एक ऐसी प्रणाली अपनानी चाहिए जिसमें-भ्रष्टाचार का जोखिम न्यूनतम,निरीक्षण डिजिटल,लाइसेंसिंग पारदर्शी, और जिम्मेदारी शीर्ष स्तर पर निश्चित हो। अत: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत वर्तमान में एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आर्थिक विकास की तेज़ रफ्तार, शहरीकरण का विस्तार, और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बढ़ती संख्या के बीच नागरिक सुरक्षा की चुनौती दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। गोवा नाइट क्लब की आग में 25 लोगों की दर्दनाक मृत्यु इस बात की चेतावनी है कि यदि हम भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और निरीक्षण तंत्र की विफलताओं को तुरंत ठीक नहीं करते, तो ऐसे हादसे भविष्य में भी सामने आते रहेंगे इसलिए आवश्यक है कि कलेक्टर-स्तरीय स्वत: संज्ञान अनिवार्य नियमित निरीक्षण,सार्वजनिक सुरक्षा चार्ट का प्रदर्शन,उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई,भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्र का सशक्तिकरण उपायों को लागू किया जाए।

-संकलनकर्ता लेखक - **किशन सनमुखदास भावनानी** गोंदिया महाराष्ट्र

आंचलिक

बोथू जंगल में तेंदुए के पगमार्क मिले स्टेट टाइगर डॉग स्क्वॉड ने की पुष्टि

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन • नर्मदा क्षेत्र में तेंदुए की लगातार चहलकदमी की घटनाओं के बाद स्टेट टाइगर डॉग स्क्वॉड ने सर्चिंग अभियान चलाया है। इंदौर से आई टीम को बोथू के जंगल में तेंदुए के पगमार्क मिले हैं, जिससे क्षेत्र में उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई है। वन विभाग अब वन्य प्राणी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे लगाएगा। इंदौर से पहुंची तीन सदस्यीय डॉग स्क्वॉड टीम ने गुरुवार को स्थानीय वन विभाग के दल के साथ मिलकर बोथू और खल बुजुर्ग गांवों के जंगलों में लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्र में गहन छानबीन की। टीम ने नर्मदा क्षेत्र के भौगोलिक स्वरूप का भी अध्ययन किया। सर्चिंग के दौरान बोथू के जंगल में तेंदुए के स्पष्ट पगमार्क पाए गए। इन पगमार्कों से बोथू क्षेत्र में तेंदुए की उपस्थिति की आधिकारिक पुष्टि हुई है, जिससे ग्रामीणों की आशंकाएं सही साबित हुई हैं।

डॉग स्क्वॉड के साथ जंगल की तलाशी ली

टीम लीडर भूषण सावलकर के नेतृत्व में डॉग स्क्वॉड ने सबसे पहले खल बुजुर्ग के जंगल में तलाशी ली। इसके बाद नर्मदा तट से लगे जंगलों और आसपास के खेतों में तेंदुए के संभावित ठिकानों की तलाश की गई। किसानों और ग्रामीणों द्वारा बताए गए स्थानों पर विशेष जांच की गई, जिसमें स्थानीय लोगों

ने भी टीम का सहयोग किया। ग्रामीणों ने बताया कि बोथू क्षेत्र में कुछ समय से तेंदुए की गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं, जिससे पशुपालकों को काफी नुकसान हुआ है। इन शिकायतों के बाद ही वन विभाग हरकत में आया और सर्चिंग अभियान शुरू किया गया। वन अमले ने बोथू के जंगल में तेंदुए की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के लिए ट्रैप कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य वन्य प्राणी के मूवमेंट पर नजर रखना है। इस अभियान में रेंजर नाहर सिंह भूरिया, तेरसिंह मौर्य, सोहेल खान सहित अन्य वनकर्मी मौजूद रहे। रेंजर नाहर सिंह भूरिया ने जानकारी दी कि नर्मदा क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है और लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

दो मंजिला बिल्डिंग गिरी, बगल में बन रहे कॉम्प्लेक्स की वजह से नींव कमजोर हुई

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा • दो मंजिला इमारत अचानक ढह गई। चंद सेकेंड में ही पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इसमें शहर का नामी थोक मेडिकल स्टोर था। गुरुवार को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण स्टोर पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। घटना पड़ावा स्थित भैरव तालाब वार्ड की है। बिल्डिंग से सटकर ही एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। जिसकी खुदाई गहरी होने से मेडिकल स्टोर की नींव कमजोर हो गई थी। पड़ोसियों ने बताया कि बिल्डिंग गिरने से पहले अचानक धूल का गुबार उठा तो वे अलर्ट हो गए। कॉम्प्लेक्स के निर्माण में लगे तीन मजदूरों को वहां से हटने को कहा।

3 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर कॉम्प्लेक्स बन रहा

इमारत के बगल में मार्केट का कंस्ट्रक्शन करा रहे खैराज लालवानी ने बताया कि यहां 3 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इंजीनियर्स ने नींव की खुदाई तब तक करने के लिए कहा था, जब तक की काली मिट्टी की सतह खत्म न हो। इसे नींव के लिए ही गहरा किया जा रहा था न कि बेसमेंट के लिए। लालवानी ने कहा- निर्माण संबंधी सभी परमिशन के लिए नगर निगम में आवेदन किए हुए ढाई महीने हो गए हैं। अधिकारी विजिट भी कर चुके हैं। परमिशन क्लियर होने में

समय लग रहा था, इस कारण हमने अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं किया था।

दो मंजिला बिल्डिंग में चल रहा था मेडिकल स्टोर

प्रत्यक्षदर्शी शोएब ने कहा- तीन आदमी साइट पर काम कर रहे थे। धुएं का गुबार उठा तो मुझे लगा कि मकान गिरने वाला है। मैं चिल्लाया। वे तीनों बाहर आ गए। करीब 19 मिनट बाद ही मकान गिर गया। स्थानीय रहवासी दिलीप यादव ने कहा- दो मंजिला बिल्डिंग में चल रहा मेडिकल स्टोर सतपाल सिंह चावला का है। उनके बेटे मंजीत चावला भी यहां बैठते हैं। हमेशा 10-12 लोगों की भीड़ रहती है। सतपाल सिंह चावला के भतीजे अमृतपाल सिंह चावला ने बताया कि मकान की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ थी। हादसे में मेडिकल स्टोर को मिलाकर कुल 5 करोड़ का नुकसान हुआ है।

बिना अनुमति काम कराने वाले बिल्डर को नोटिस

नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने बताया कि इस प्रकरण में संबंधित कार्यपालन यंत्री, उपयंत्री, टाइम कीपर और सहायक राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उनके स्पष्टीकरण मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति काम कराने वाले बिल्डर को भी नोटिस जारी किया गया है।

प्रदेश गवर्नर का निमाड़ दौरा, कलेक्टर का निरीक्षण, 23 को आएंगे मंगूभाई पटेल

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन • मप्र के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का निमाड़ दौरा प्रस्तावित है। वे 23 दिसंबर को खरगोन जिले के पानवा आएंगे। यहां वे सिकलसेल शिविर और आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे सिंगाजी टेकड़ी बलखड़ भी जाएंगे।

प्रशासन ने उनके दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने स्कूल परिसर और सिंगाजी टेकरी का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ आकाश सिंह, पूर्व विधायक आत्माराम पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्रसिंह तंवर भी मौजूद थे।

बड़वानी में करेंगे रात्रि विश्राम, फिर बुरहानपुर जाएंगे

हालांकि, राज्यपाल के दौरे का अधिकृत विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि वे 24 दिसंबर को बड़वानी जिले के कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। वहां रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन वे बुरहानपुर के लिए रवाना होंगे।

छात्र जीवन के लिए महत्वपूर्ण है शिक्षा, खेल, योग

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन • शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। सरपंच उर्मिला मालाकार ने कहा छात्र जीवन में शिक्षा, खेल व योग को समय देने वाले सफल होकर स्वयं के उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। साथ ही देश, ग्राम, संस्था व परिवार को गौरवांवित करते हैं। सांसद खेल महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य है कि ग्रामीण प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जिला, राज्य व देश स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। वर्तमान समय में बच्चे पारंपरिक खेलों से दूर होते जा रहे हैं। इससे उनका मानसिक विकास तो तेजी से हो रहा है, लेकिन

शारीरिक विकास अपेक्षानुसार नहीं हो रहा है। इसलिए सभी छात्र-छात्राएं अपने शैक्षणिक कार्य के साथ पारंपरिक खेलों में भी समय दें। संकुल प्रभारी केके डोंगरे ने बताया महोत्सव के तहत संकुल केंद्र के 338 बच्चों ने पंजीयन कराया था। उपसरपंच सुरेंद्र मालाकार, शिक्षक धर्मेंद्र मुकाती, निश्चल गुप्ता, सुदामा भारती, वीरेंद्र सिंह सोलंकी आदि मौजूद थे।

अहमदाबाद में निर्णायक मुकाबला आज

अहमदाबाद (एजेंसी) ● भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी रोमांचक टी20 सीरीज का 5वां और निर्णायक मुकाबला आज शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। लखनऊ में चौथा मैच कोहरे की भेंट चढऩे के बाद भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है। ऐसे में देखना खास रहेगा कि टीमों को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कैसा विकेट मिलता है। अगर मौसम की बात करें तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अहमदाबाद में कोहरे की कोई संभावना नहीं है। वहां आसमान साफ रहेगा और तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। यानी मौसम बिल्कुल ठीक रहेगा और पूरा मैच खेला जाएगा। इसके अलावा अहमदाबाद की पिच अपनी विविधता के लिए जानी जाती है, लेकिन टी20 क्रिकेट में यहां अमूमन बल्लेबाजों का दबदबा रहता है।

यहां की आउटफील्ड बहुत तेज है और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे बड़े स्कोर बनने की पूरी संभावना है। आंकड़ों के अनुसार, इस मैदान पर स्पिनरों की तुलना में तेज गेंदबाजों को अधिक विकेट मिलते हैं। शुरुआत में नई गेंद से स्विंग मिलने की उम्मीद है। दिसंबर की ठंड के कारण शाम को ओस गिरने की काफी संभावना रहती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि दूसरी पारी में गीली गेंद से ग्रिप बनाना मुश्किल हो जाता है। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दोनों टीमों का रिकॉर्ड काफी कड़ा रहा है, लेकिन भारत का पलड़ा थोड़ा भारी है। अहमदाबाद का यह मैदान हाई-स्कोरिंग मैचों के लिए मशहूर है। यह मैच दक्षिण अफ्रीका के लिए सीरीज ड्रॉ कराने का आखिरी मौका है, जबकि टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी।

अब मौसम देखकर बनाए जाएंगे आगे के शेड्यूललखनऊ। लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच घने कोहरे के कारण रद्द करना पड़ा था। कोहरा इतना घना था कि टॉस भी नहीं हो सका। मैच रद्द होने के बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीसीसीआई अब भविष्य की शेड्यूलिंग में मौसम और प्रदूषण को ज्यादा गंभीरता से लेगा। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने स्वीकार किया कि मैच रद्द होना बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि लखनऊ टी20 मैच कैंसिल हुआ और इससे सभी निराश हैं।

रेड कार्पेट पर आलिया, अभिषेक, विक्की , सिद्धांत प्रतिभा रांटा सहित कई चर्चित चेहरे नजर आए

मुंबई (एजेंसी) ● नेशनल फिल्मफेयर मुंबई के जुहू स्थित जेडब्ल्यू मैरियट में फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 का भव्य आयोजन किया। आयोजन हुंडई और ब्लेंडर्स प्राइड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के को-पावर्ड सहयोग से संपन्न हुआ। इस साल का संस्करण डिजिटल एंटरटेनमेंट के बदलते स्वरूप का जश्न मनाने के लिए देश के नामी सितारों, क्रिएटर्स और स्टोरीटेलर्स को एक मंच पर लेकर आया। अवार्ड समारोह में 1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 के बीच रिलीज हुई वेब ओरिजिनल सीरीज और फिल्मों में बेहतरीन काम को सम्मानित किया गया। शाम के बड़े विजेताओं में ब्लैक वारंट ने बेस्ट सीरीज का खिताब अपने नाम किया, वहीं गर्ल्स विल बी गर्ल्स को बेस्ट फिल्म, वेब ओरिजिनल का अवॉर्ड मिला। कॉमेडी कैटेगरी में रात जवान है को बेस्ट कॉमेडी (सीरीज.स्पेशल्स) चुना गया। यह सम्मान उन रचनात्मक कोशिशों को रेखांकित करता है, जिन्होंने इस साल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कहानी कहने के स्तर को और ऊंचा किया। शाम के सबसे बड़े विजेताओं के तौर पर खौफ 7 अवॉर्ड्स के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद स्टोलन और ब्लैक वारंट को 6.6 अवॉर्ड मिले। पाताल लोक सीजन 2 ने 5 अवॉर्ड अपने नाम किए, जबकि गर्ल्स विल बी गर्ल्स को 4 अवॉर्ड मिले। सेक्टर 36 और सीटीआरएल को 3.3 अवॉर्ड हासिल हुए, वहीं फ्रीडम एट मिडनाइट और आईसी 814. द कंधार हाईजैक को 2.2 अवॉर्ड मिले। इस दौरान व्यक्तिगत कैटेगरी में भी कई अहम जीत देखने को मिलीं। जयदीप अहलावत, अभिषेक बनर्जी, सान्या मल्होत्रा, फातिमा सना शेख, विक्रांत मैसी, अनन्या पांडे और बोमन ईरानी ने प्रतिष्ठित ब्लैक लेडी अपने नाम की। टेक्निकल कैटेगरी में पंकज कुमार, तान्या छाबड़िया और बिग्याना दहल जैसे नामों को भी सम्मान मिला। ये सभी अवॉर्ड्स इंडस्ट्री की क्वालिटी और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस के प्रति लगातार कोशिशों को दिखाते हैं और भारत के ओटीटी इकोसिस्टम की मजबूती और विकास को रेखांकित करते हैं। औपचारिक सम्मान के साथ.साथ शाम में कई भावुक और यादगार पल भी देखने को मिले। अभिषेक बच्चन ने तब खूब तालियां बटोरीं, जब उन्होंने दर्शकों के बीच से एक कुर्सी उठाकर बोमन ईरानी के लिए मंच पर रखी और अपने निजी फोन से उनका एक्सेप्टेंस स्पीच रिकॉर्ड किया। इसके बाद बोमन ईरानी का भावनात्मक भाषण शाम का खास आकर्षण बन गया, जिसमें उन्होंने विश्वास, कहानी कहने की ताकत और सिनेमा के जरिए पर्दे से आगे जुड़ाव, उपचार और प्रेम की बात कही। जयदीप अहलावत ने अपना अवॉर्ड अपने दिवंगत पिता को समर्पित करते हुए बेहद भावुक भाषण दिया और कहा कि उन्हें आज भी विश्वास है कि उनके पिता उन्हें ऊपर से देख रहे हैं, जिससे दर्शक भावुक हो उठे। अभिषेक बनर्जी ने अवॉर्ड लेते हुए बताया कि वे लगातार अमिताभ बच्चन से प्रेरित रहते हैं। उन्होंने याद किया कि लॉकडाउन से पहले ही उन्होंने स्टोलन प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी थी, क्योंकि उन्हें कहानी पर पूरा भरोसा था, और शूट से सीधे अवॉर्ड लेने पहुंचने की खुशी भी साझा की। अनन्या पांडे ने अपना अवॉर्ड लेते हुए महिलाओं द्वारा अपनी पहचान और फैसलों को अपनाने की बात कही और बताया कि यह सम्मान उन्हें अपनी आवाज और रास्ते पर भरोसा रखने की ताकत देता है। विक्रांत मैसी का भाषण भी गहराई से जुड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी जीत को सामाजिक और आर्थिक हाशिये पर रहने वाली आवाजों को समर्पित किया और ऐसी कहानियों को आगे भी सामने लाने का संकल्प लिया। इस शाम कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियां भी दर्ज हुईं, जब फातिमा सना शेख ने आयशा के लिए अपना पहला फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता और रसिका दुग्गल को शेखर होम के लिए पहला फिल्मफेयर सम्मान मिला। इस तरह यह रात टैलेंट, उद्देश्य और असरदार कहानी कहने का यादगार उत्सव बन गई।

लियोन टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने

एडीलेड (एजेंसी) ● ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने यहां एडिलेड में खेले जा रहे तीसरे एशेज क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरा विकेट लेते ही एक अहम उपलब्धि अपने नाम कर ली है। अब लियोन टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गये हैं। वहीं विश्व स्तर पर टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज बने हैं। उन्होंने इससे पहले नंबर एक पर रहे दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा को सबसे अधिक विकेट के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब उनसे आगे केवल दिवंगत महान स्पिनर शेन वॉर्न ही हैं। वार्न ने अपने करियर में 708 विकेट टेस्ट क्रिकेटर में लिए थे। तीसरे टेस्ट की पहली पारी मे लियोन ने इंग्लैंड के डकेट को बोल्ड कर मैक्ग्रा को विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर धकेल दिया। उसी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में उनके विकेटों की तादाद 564 पहुंच गई और वह ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इस मैच से पहले तक मैक्ग्रा ने टेस्ट क्रिकेट में 563 विकेट लिए थे। लियोन ने पहले ओली पोप और उसके बाद डकेट को आउट किया। लियोन अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में छठे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उनसे आगे इस सूची में श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, भारत के अनिल कुंबले और इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड शामिल हैं। मुरलीधरन ने 800, वॉर्न ने 708, एंडरसन ने 704, कुंबले ने 619 और ब्रॉड ने 604 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं।

हॉकी इंदौर एसोसिएशन टीम के लिए चयन ट्रायल्स 20 दिसंबर को

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● हॉकी इंदौर एसोसिएशन के सचिव किशोर शुक्ला व सहसचिव मो याकुब अंसारी ने बताया कि दिनांक 24 दिसंबर 2025 से हॉकी मध्यप्रदेश द्वार बालाघाट मे आयोजित मध्यप्रदेश स्टेट हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई है स्टेट चैंपियनशिप के लिए हॉकी इंदौर एसोसिएशन टीम के लिए दिनांक 20 दिसंबर को स्थानीय चिमनबाग हॉकी मैदान पर शाम 4 बजे से चयन ट्रायल्स आयोजित की गई है चयन ट्रायल्स मे भाग लेने वाले इच्छुक खिलाड़ी मैदान पर एन आई एस कोच अतुल खुणे ,नितिश गौड से संपर्क कर सकते हैं।

बार-बार देखने का मन करता है 'धुरंधर': एलनाज

मुंबई (एजेंसी) ● फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। पिछले 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म की इंडस्ट्री के सितारे भी जमकर सराहना कर रहे हैं। हाल ही में ईरानी मूल की अभिनेत्री और मॉडल एलनाज नौरोजी ने भी 'धुरंधर' की खुलकर तारीफ की है। एलनाज नौरोजी ने फिल्म की प्रशंसा के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी सेक्शन का सहारा लिया। उन्होंने 'धुरंधर' का पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं। एलनाज ने न सिर्फ फिल्म की कहानी की तारीफ की, बल्कि निर्देशक आदित्य धर और पूरी स्टारकास्ट को भी सराहा। उन्होंने लिखा कि फिल्ममेकिंग अपने बेहतरीन स्तर पर नजर आती है और आदित्य धर ने एक बार फिर खुद को साबित किया है। इसके साथ ही उन्होंने रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना की एक्टिंग को बेजोड़ बताया।

उज्जैन संभाग

अजाक्स का संतोष वर्मा के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना, 20 दिसंबर को रैली की चेतावनी

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ●फ्रीगंज टावर चौक स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर अजाक्स संगठन ने आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। संगठन संतोष वर्मा को पद से हटाए जाने की कार्रवाई वापस लेने की मांग कर रहा है। धरने से पहले कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर नारेबाजी भी की। डॉ. अंबेडकर विद्यार्थी संगठन के राम सोलंकी ने बताया कि आईएएस संतोष वर्मा ने 23 नवंबर 2025 को तुलसीनगर स्थित अंबेडकर मैदान में अजाक्स संगठन के प्रांतीय अधिवेशन में मंच से संबोधित करते हुए कोई आपत्तिजनक या गलत बयान नहीं दिया था। उनके उद्बोधन को जानबूझकर तोड़-मरोड़ कर भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगठन का आरोप है कि शासन ने बिना उचित विचार-विमर्श, तथ्यों की निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना संतोष वर्मा पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के विरोध में यह धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से मांग की गई है कि संतोष वर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई को तत्काल वापस लिया जाए।

विभिन्न संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस नहीं ली गई, तो 20 दिसंबर को उज्जैन में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धरने में अजाक्स संगठन, भीम आर्मी, भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, डोमा परिसंघ, आजाद समाज पार्टी, गुजराती बलाई युवा संगठन, मालवीय बलाई समाज संगठन, रविदास सेवक संघ और गुजराती सूर्यवंशी समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्राह्मण बेटियों को लेकर अपशब्द कहने वाले और हाईकोर्ट पर एससी-एसटी को सिविल जज नहीं बनने देने का आरोप लगाने वाले आईएएस एवं अनुसूचितजाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के अध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ मप्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव भेजा है। सरकार के इस कदम के बाद सवर्ण समाज ने सीएम हाउस का घेराव 10 दिन के लिए टाल दिया है। घेराव रविवार को होना था।

भाजपा नेता का नामांकन निरस्त, एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना, प्रशासन से लिखित जवाब की मांग

दैनिक इंदौर संकेत

आगर - मालवा ● सुसनेर में जिला पंचायत सदस्य चुनाव के दौरान वार्ड क्रमांक 1 से भाजपा नेता मोहन सिंह का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। इसके विरोध में मोहन सिंह ने गुरुवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और प्रशासन से लिखित जवाब की मांग की। सुसनेर के वार्ड क्रमांक 1 में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आगामी दिनों में चुनाव होने हैं। इसके लिए कई प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम सुसनेर के समक्ष अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए थे। नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तिथि 16 दिसंबर निर्धारित थी, इसी दौरान मोहन सिंह का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। नामांकन निरस्त होने की सूचना मिलने पर मोहन सिंह पिता बापू सिंह ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नामांकन पत्र को किन ठोस कारणों से निरस्त किया गया, इसकी लिखित जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है। उन्होंने प्रशासन पर पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर चुनाव से बाहर करने की साजिश रची जा रही है।

इस मामले पर एसडीएम सर्वेश यादव ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ हाईकोर्ट में एक प्रकरण लंबित है। इसी कारण वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा एवं मार्गदर्शन के बाद नामांकन निरस्त करने का निर्णय लिया गया। एसडीएम यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में मोहनसिंह द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना देना नियमों के खिलाफ और अवैधानिक है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा सभी कार्रवाई नियमानुसार की गई है।

महाकाल मंदिर में गेट एक से प्रवेश व्यवस्था बदली, निर्माण कार्य के कारण शहनाई द्वार से श्रद्धालु करेंगे प्रवेश

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● श्री महाकालेश्वर मंदिर में नववर्ष पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रवेश व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों के कारण गेट क्रमांक एक (अवंतिका द्वार) को शहनाई द्वार की ओर स्थानांतरित कर दिया गया है। श्रद्धालु अब इसी नए मार्ग से प्रवेश कर दर्शन कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था गुरुवार से लागू हो गई है। अवंतिका द्वार को उसके वर्तमान स्थान से हटाकर शहनाई द्वार, पालकी निर्गम स्थल के पास स्थापित किया गया है। यहां से प्रवेश करने वाले श्रद्धालु फेसिलिटी सेंटर से होते हुए भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे।

इसके अतिरिक्त, बड़ा गणेश मंदिर के पास स्थित एंबुलेंस निर्गम द्वार पर एक नया शीघ्र दर्शन टिकट काउंटर भी शुरू किया गया है। यहां से श्रद्धालु 250 रुपए का टिकट लेकर प्रवेश कर सकेंगे। टिकटधारी श्रद्धालु गणेश मंडप से भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर निर्धारित निर्गम द्वार से बाहर निकलेंगे। नवीन प्रवेश द्वारों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लॉकर, जूता-स्टैंड और मेटिंग जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दर्शन मार्ग को छोटा और सुगम बनाया गया है, जिससे भक्तों को शीघ्र और सहजता से दर्शन लाभ मिल सके। श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने गुरुवार को मंदिर परिसर के आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों सहित रुद्र सागर क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा तथा सुचारू दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रशासक ने नए प्रवेश और निर्गम गेट की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की।

सीएम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 1.5 लाख पाठ होगा, 20 दिसंबर को आयोजन

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● 20 दिसंबर को 1.51 लाख हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से इंदौर रोड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। जिसमें बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद अनिल फिरोजिया, अभिनेत्री एवं सांसद हेमा मालिनी सहित अनेक संत, महंत, महामंडलेश्वर, शिक्षाविद, चिकित्सक और विभिन्न समाजों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष दुर्गेश नंदिनी शर्मा एवं आयोजन समिति अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चावड़ा ने बताया कि इस अवसर पर 1008 हनुमान मंदिरों के ध्वजों की महाआरती भी की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीराम धुन से होगी, जिसके बाद सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ संपन्न कराया जाएगा।

कांग्रेस ने विजय शाह का पुतला फूंका, लाड़ली बहनों पर टिप्पणी का किया विरोध, इस्तीफे की रखी मांग

दैनिक इंदौर संकेत

आगर - मालवा ● आगर मालवा में लाड़ली बहनों को लेकर मंत्री विजय शाह की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री शाह का पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग की। छावनी नाका पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजयलक्ष्मी तंवर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया।

जिलाध्यक्ष बोलीं-यह बयान बेहद अशोभनीय

कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजयलक्ष्मी तंवर ने कहा कि मंत्री विजय शाह का लाड़ली बहनों के संबंध में दिया गया बयान बेहद अशोभनीय है और यह महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री का यह कहना कि यदि लाड़ली बहनें सभा में शामिल नहीं हुईं तो उनकी जांच कराई जाएगी, यह दर्शाता है कि सरकार महिलाओं को दबाव और भय के माध्यम से नियंत्रित करना चाहती है। जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि लाड़ली बहनें किसी की खरीदी हुई नहीं हैं, वे स्वाभिमान के साथ अपने परिवार का संचालन करती हैं। उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी को महिलाओं की गरिमा पर सीधा हमला बताया, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह से तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की।

इस्तीफा न मिलने पर आंदोलन की दी चेतावनी

कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मंत्री द्वारा शीघ्र इस्तीफा नहीं दिया गया, तो पार्टी प्रदेश स्तर पर आंदोलन को तेज करेगी। इसमें भोपाल में मुख्यमंत्री के घेराव जैसा बड़ा कदम भी शामिल होगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने मंत्री के बयान की निंदा करते हुए महिलाओं के सम्मान की रक्षा का संकल्प दोहराया।

शहर में ट्रैफिक ई-चालान के नाम पर डिजिटल फ्राड का नया तरीका, एक क्लिक में खाली हो रहा बैंक अकाउंट

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● बदलते समय के साथ सायबर ठग भी ठगी के तरीके बदल रहे हैं। इंदौर में एक और नया तरीका निकालते हुए सायबर अपराधियों को ट्रैफिक ई-चालान को नया हथियार बना लिया है। व्हाट्सएप के जरिए फर्जी ई-चालान भेजकर लोगों का मोबाइल हैक किया जाकर उनके साथ ठगी की जा रही है।

असली ई - चालान जैसे मैसेज-साइबर अपराधियों द्वारा भेजे जा रहे ये मैसेज देखने में बिल्कुल ट्रैफिक विभाग के असली ई-चालान जैसे लगते हैं। रेड सिग्नल जंप, ओवरस्पीड या ट्रैफिक नियम तोड़ने के नाम पर भेजी गई फर्जी पीडीएफ या एपीके फाइल लोगों को भ्रमित कर रही है।

हैक हो जाता है मोबाइल-जैसे ही कोई व्यक्ति इसे खोलता है, उसका मोबाइल फोन हैक हो जाता है। ठग फोन में मौजूद बैंकिंग, यूपीआई और निजी डेटा तक पहुंच बना लेते हैं।

बड़े नाम भी बने निशाना-इस नए साइबर फ्रॉड की चपेट में आम नागरिक ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी आ चुके हैं। हाल ही में बजरंग दल के एक पदाधिकारी को इसी तरह का फर्जी ई-चालान भेजा गया। उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी को भी

फर्जी ई-चालान भेजा गया था, हालांकि अधिकारी की सतर्कता से बड़ा नुकसान टल गया।

जगदीश सिंह कुशवाह ने बताया कि मेरा व्हाट्सएप बुधवार रात को हैक हुआ था। इस दौरान मेरे व्हाट्सएप नंबर से ठगो ने मेरे कॉन्टेक्ट नंबर के परिचितों को ई चालन के मेसेज भेजते हुए ठगी का प्रयास किया। मामले में मैने थाने पर शिकायत करते हुए व्हाट्सएप रिकवर कर लिया है।

ऐसे होती है ट्रैफिक ई-चालान से ठगी

व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से ई-चालान का मैसेज भेजा जाता है। मैसेज में पीडीएफ-एपीके फाइल अटैच रहती है। फाइल खोलते ही मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद बैंक अकाउंट, यूपीआई और सोशल मीडिया तक पहुंच बनाकर अकाउंट खाली कर दिया जाता है।

ठगों की चालाकी-सायबर ठग इतने शातिर हैं कि असली ई-चालान जैसा फॉर्मेट भेजते हैं, जिसमें सरकारी भाषा और लोगो का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही डर पैदा करने वाला मैसेज भेजा जाता है, जिससे तुरंत भुगतान का दबाव बन सके। इसी वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं और ठगों के जाल में फंस जाते हैं।

इस साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके-संदेश की प्रमाणिकता जांचें: अगर कोई ई-चालान आपको मिलता है, तो पहले इसकी प्रमाणिकता की जांच करें। किसी भी अनजान लिंक या अटैचमेंट को खोलने से बचें।

सतर्कता बनाए रखें- अगर संदेश में किसी प्रकार का डर पैदा किया जाता है या किसी जल्दी में भुगतान करने का दबाव डाला जाता है, तो उसे नजरअंदाज करें।

न्यूज ब्रीफ

पूर्वी आउटर रिंग रोड के खिलाफ 38 गांव के किसानों का प्रदर्शन

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर में पूर्वी आउटर रिंग रोड के प्रस्तावित एलाइनमेंट के विरोध में किसानों ने रीगल तिराहे पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि इस हाईवे परियोजना से 38 गांवों की उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित हो रही है, जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। किसानों ने मांग की कि रिंग रोड को वर्तमान बाईपास से 20-25 किलोमीटर दूर या सरकार द्वारा पहले सर्वे किए गए 161 किलोमीटर वाले एलाइनमेंट पर बनाया जाए, जहां अधिकतर भूमि बंजर और शासकीय है। उनका आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि मौजूदा एलाइनमेंट नहीं बदला गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन ने भी किसानों को समर्थन दिया और उचित मुआवजे की मांग की।

चाइनीज मांझा बेचने वाले वालों के विरुद्ध पुलिस की प्रभावी कार्यवाही

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर शहर मे चाइनीज मांझा के क्रय विक्रय करने वालों की धरपकड़ करने एवं वैधानिक कार्यवाही के निर्देश पुलिस आयुक्त महोदय नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय अमित सिंह, पुलिस उपायुक्त महोदय झोन 02 कुमार प्रतीक, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त झोन 02 अमरेन्द्र सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त खजराना कुंदन मण्डलोई द्वारा थाना खजराना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव को दिये गये है । थाना प्रभारी खजराना द्वारा एक टीम गठित कर चाइनीज मांझे का कार्य विक्रय करने की धर पकड़ हेतु लगाया गया जिसमें मुखबिरी सूचना पर खजराना में चाइनीज मांझा के साथ दो आरोपी मोहन कुशवाह, धीरज नगर खजराना एवं गोविंद गुप्ता काछी मोहल्ला को विधिवत अभिरक्षा में लेकर चाइनीज मांझा जप्त किया।

ईडी में फंसे गुटखा किंग किशोर वाधवानी पत्नी, सीईओ और दबंग दुनिया कंपनी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मध्यप्रदेश में सबसे बड़े टैक्स डिमांड 2002 करोड़ का नोटिस हाल ही में गुटखा किंग किशोर वाधवानी को मिला था। वहीं, अब किशोर वाधवानी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इंदौर में उलझ गए हैं। सेंट्रल जीएसटी और एक्साइज कमिश्नरेट की कार्रवाई के दौरान ही वाधवानी पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी मामला आया था। यह मामला समाचार पत्र दबंग दुनिया के नाम पर हुआ था। इसी मामले में तुकोगंज थाने में भी चार सौ बीसी व अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इसी एफआईआर को लेकर ईडी ने वाधवानी व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत किया गया है।

ईडी ने दबंग दुनिया के नाम पर हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज करने के बाद जांच की थी। वहीं, अब इसमें स्पेशल कोर्ट ईडी में चालान पेश कर दिया है। इसमें मेसर्स दबंग दुनिया प्रा.लि., ऑफिस 307 और शालीमार कॉर्पोरेट सेंटर साउथ तुकोगंज इंदौर को आरोपी बनाया गया है। इनके साथ ही किशोर वाधवानी पिता खेमचंद वाधवानी, 65 बी प्रेम नगर इंदौर और पूनम वाधवानी पत्नी किशोर वाधवानी को आरोपी बनाया गया है। इनमें पंकज मजेपुरिया भी शामिल है। डीजीसीआई (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन) ने 10 फरवरी 2021 को तुकोगंज थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी धारा लगाई गई थी। इसमें किशोर वाधवानी का नाम था। बाद में ईडी ने जांच कर उनकी पत्नी पूनम और दबंग दुनिया के सीईओ पंकज मजेपुरिया को भी आरोपी बना दिया। ईडी और डीजीसीआई की जांच में पता चला कि दबंग दुनिया समाचार पत्र की प्रतियों की बिक्री हर दिन 60 हजार से 1 लाख बताई गई थी, जबकि यह केवल 5 से 8 हजार मात्र थी। इसके एवज में इनके द्वारा अन्य व्यवसाय से हुई कमाई/काले धन को नकद बिक्री दिखाकर दबंग दुनिया के खाते में जमा किया जाता था। जांच में यह भी पाया गया कि इनके जरिए विज्ञापनों से फर्जी आय दिखाई जाती थी। साथ ही, कूटरचित टैक्स इनवॉयस बनाए जाते थे। इसके लिए फर्जी लेन-देन भी दिखाया जाता था। इससे यह सरकार और अधिकारियों की पकड़ में न आ सकें। इन विज्ञापनों को छापा नहीं जाता था, बल्कि इनका उपयोग केवल अपनी काली कमाई को वैध आय बताने के लिए किया जाता था। ईडी और डीजीसीआई की जांच में यह सामने आया कि दबंग दुनिया के जरिए वाधवानी और अन्य ने 11.66 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। यह मनी लॉन्ड्रिंग वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान की गई थी। इस अवधि में बताया गया कि दबंग दुनिया की 2.80 करोड़ कापियां बिकी हैं। साथ ही, दो रुपए प्रति कॉपी के हिसाब से 5.73 करोड़ की आय हुई है। जांच में पाया गया कि घनश्याम दास का 25 लाख का विज्ञापन छपा ही नहीं था। इसके अलावा, मित्र मंडल के नाम से कई फर्जी इनवॉयस जारी किए गए थे। ये सभी इनवॉयस असल में विज्ञापन थे ही नहीं। इसी तरह सर्कुलेशन में पांच से आठ गुना अधिक बढ़ोतरी दिखाकर इसकी कॉपी बेचकर कमाई होना बताया गया है।

जिस मकान में पूरी तरह शिफ्ट भी नहीं हुए, वहां करोड़ों का माल

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

उज्जैन ● यदि आपके पास कुछ लाख की नकद धनराशि है तो उसे आप कहां रखकर सुरक्षित महसूस करेंगे। घर में या बैंक के लॉकर में या खुद ऐसे स्थान पर जहां आप खुद ज्यादा से ज्यादा समय मौजूद रहेंगे। मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात इंदौर रोड स्थित अमरनाथ एवेन्यू में हुई चोरी की घटना में ऐसा नहीं है। जिस मकान में गोयल परिवार पूरी तरह से शिफ्ट भी नहीं हुआ था वहां करोड़ों की चोरी होने की जानकारी सामने आई। इस अहम सवाल को बिंदु बनाकर पुलिस अब जांच का दायरा ऐसे लोगों पर केंद्रित कर रही है जिन्हें घर के बारे में पूरी जानकारी हो सकती थी।

सरकारी कामों का ठेका लेने वाले आनंद गोयल के घर पर हुई चोरी की घटना में शुरुआती जांच में करीब 70 लाख रुपए नकद व 80 तोला सोने के आभूषण चोरी होने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों की माने तो फिलहाल पुलिस को गोयल परिवार ने चोरी गए सामान की अधिकृत जानकारी नहीं सौंपी है। अभी तो वे खुद ही हिसाब-किताब लगा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम बात सामने आई है। आनंद गोयल खुद इंदौर शिफ्ट हो चुके है। उनके पिता पुरुषोत्तम गोयल और मां बसंत बिहार कॉलोनी के एक घर में किराए के मकान में रहते थे। कुछ महीने पहले ही आनंद गोयल ने अमरनाथ एवेन्यू कॉलोनी में मकान खरीदा था। बातचीत में यह भी सामने आया कि खुद गोयल परिवार की मुखिया महिला को नई लोकेशन में रहना पसंद नहीं था, यहां तक की गोयल परिवार का पूरा सामान भी बसंत विहार से अमरनाथ एवेन्यू के नए मकान में शिफ्ट नहीं हुआ है। घटना की रात भी वृद्ध दंपत्ति बसंत विहार में अपने पुराने मकान में थे। जिस मकान में घर का सामान भी पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो पाया, खुद आप ज्यादातर समय पुराने बसंत विहार के मकान में बिता रहे हैं तो फिर नए और सूने मकान में लाखों का कैश, करोड़ों की ज्वेलरी असुरक्षित कौन छोड़ सकता है।

महाकाल लोक की तर्ज पर संवरेगा प्राचीन नवग्रह शनि मंदिर

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

उज्जैन ● त्रिवेणी स्थित नवग्रह शनि मंदिर को अब महाकाल महालोक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा जिस पर 140 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शनि उपासना, त्रिवेणी घाट और शिप्रा तट इसमें शामिल करते हुए शहर में दूसरा बड़ा धार्मिक कारिडोर आकार लेगा जो शहर की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा, पर्यटन क्षमता और आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देगा। मप्र सरकार ने शनि लोक निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी है जो सिंहस्थ-2028 की तैयारियों में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी नवग्रह शनि मंदिर करीब 21100 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं सम्राट विक्रमादित्य ने की थी और इसी पवित्र स्थल से विक्रम संवत की शुरुआत भी मानी जाती है। हर शनि अमावस्या पर क्विंटलों से शनिदेव का अभिषेक होता है और दूर-दर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर की आस्था और आकर्षण दोनों बढ़ते हैं। नया 'शनि लोक' बनने के बाद धार्मिक विकास के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगा।

नारायणा में बनेगा 'श्रीकृष्ण-सुदामा लोक'- उज्जैन को दो और सौगात मिलने जा रही है। उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील से करीब 9 किमी दूर स्थित नारायणा धाम को 'श्रीकृष्ण-सुदामा लोक' और भगवान श्रीकृष्ण के शिक्षा स्थल सांदीपनि आश्रम को आधुनिक वैदिक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की 201 करोड़ की योजना को प्राथमिकता में रखा है। नारायणा धाम पर 120 करोड़ रुपए से बाल्य कथा प्रांगण, मूर्ति-शिल्प, स्मृति वन, ओपन एयर थियेटर और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित होंगी, जबकि सांदीपनि आश्रम में 81 करोड़ रुपए से ध्यान क्षेत्र व ईको कैम्पस तैयार होगा। इन स्थलों से श्रीकृष्ण-सुदामा की ऐतिहासिक कथा और गुरु-शिष्य परंपरा को आधुनिक रूप में अनुभव किया जा सकेगा। दोनों धार्मिक स्थल श्रीकृष्ण पाथेय योजना का हिस्सा हैं। यह विकास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन मानचित्र में मजबूत स्थान दिलाएगा।

यहां श्रीकृष्ण की सुदामा से मित्रता हुई

नारायण धाम में श्रीकृष्ण मंदिर है। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जिसमें श्रीकृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ विराजते हैं। नारायण धाम मंदिर में कृष्ण-सुदामा की अटूट मित्रता को पेड़ों के प्रमाण के तौर में भी देख सकते हैं।

महाकाल लोक के बाद पर्यटन को लगे पंख

वर्ष 2022 में हुए महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद से पर्यटन को पंख लग गए हैं। लोकार्पण के बाद से अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शहर पहुंचे हैं जिससे होटल, परिवहन, रोजगार और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। सिंहस्थ-2028 के लिए शहर को नए पर्यटन मॉडल पर तैयार किया जा रहा है जिसमें शनि लोक भी प्रमुख धुरी बनेगा। इस परियोजना से शहर की आध्यात्मिक पहचान और मजबूत होगी।

सड़क चौड़ीकरण में आने वाली मल्टी और बड़ी होटल भी आएगी चपेट में

विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत सड़क निर्माण का शुभारंभ आज

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत 16.76 करोड़ रु. की लागत से मास्टर प्लान की सड़क भमोरी चौराहे से एमआर - 10 एवं राजशाही गार्डन से होटल वॉव तक सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ शुक्रवार को होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस सड़क की चौड़ीकरण में बाधक के रूप में एक बड़ी मल्टी और होटल भी आ रही है। इस होटल और मल्टी की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ निगम के जनकार्य प्रभारी ने मोर्चा खोलेते कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। वहीं बड़ा सवाल है कि आलीशान होटल और मल्टी के बाधक हिस्से को तोड़ना निगम के लिए आसान होगा, यह आने वाला समय बताएगा।

जन कार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं विधायक रमेश मेंदोला द्वारा 19 दिसंबर को प्रात: 10 बजे भमोरी प्लाजा भमोरी चौराहा के पास विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत लागत राशि रु. 16.76 करोड़ से भमोरी चौराहे से एम. आर. 10 एवं राजशाही गार्डन से होटल वॉव तक सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर सभापति मुन्ना लाल यादव, जन कार्य प्रभारी, पार्षद ज्योति पवार, पूजा पाटीदार एवं अन्य उपस्थित रहेंगे।

इस सड़क को लेकर लिखे गए जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर की शिकायत पत्र के कारण निगम के गलियारों में हचलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कमिश्नर नगरीय प्रशासन, महापौर और कमिश्नर नगर निगम इंदौर को शिकायत की है कि सड़क की सरहद में शॉपिंग मॉल और इमारत आ रही है। इसका नक्शा पास करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नक्शे रद्द करें। उनका कहना है कि मास्टर प्लान की 23 सड़कों को बनाने के लिए केंद्र सरकार से पैसा मिला है। पैकेज-2 में जो सड़कें ली गई हैं, उसमें 11 सौ मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी सड़क भमोरी चौराहा से एमआर 10 और राजशाही गार्डन से होटल 'वॉव' तक बननी है। इसी मान से सड़क का लाइनमेंट किया जा रहा है।

सस्पेंड सहायक आयुक्त आबकारी मंदाकिनी दीक्षित ने बचाव में उतारी वकीलों की फौज, अभी राहत नहीं

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● देवास की सहायक आयुक्त आबकारी मंदाकिनी दीक्षित शराब ठेकेदार से रिश्वत मांगने के आरोप में सस्पेंड हो चुकी हैं। वह पांच दुकानों के बदले हर महीने 7.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही थीं। मध्यप्रदेश शासन के 6 दिसंबर के सस्पेंशन आदेश को चुनौती देते हुए दीक्षित हाईकोर्ट इंदौर पहुंची हैं। इस मामले में गुरुवार, 18 दिसंबर को करीब आधा घंटा बहस हुई है। दीक्षित ने बचाव के लिए 9 वकीलों को उतारा है। इस पर खुद हाईकोर्ट जस्टिस ने आश्चर्य जताया और कहा कि एक याचिकाकर्ता के लिए इतने अधिवक्ता।

दीक्षित की ओर से हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने गुरुवार को पैरवी की है। वहीं याचिका के अनुसार साथ में उनके अधिवक्ता मनु माहेश्वरी, शंशाक शेखर राय, रितेश शर्मा, आयुष्मान गुप्ता, स्मृति शर्मा, देव सिंह, यश अग्रवाल, कुणाल चंदेल और पियूष पाराशर हैं। इसमें दीक्षित ने मप्र शासन प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर, उप सचिव व आबकारी आयुक्त को पक्षकार बनाया है। दीक्षित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने तर्क रखे। इसमें बताया गया कि इंदौर के दिनेश मकवाना ने देवास में शराब ठेके लिए हैं। इनके जरिए सितंबर माह में एक वीडियो बनाया गया था। इसमें दीक्षित पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए गए थे। वहीं, मकवाना ने सुसाइड 8 नवंबर को किया था। इसके बाद 9, 11 और 16 नवंबर को मकवाना के रिश्तेदार बृजेश और उनकी मां संतोषबाई ने प्रेम यादव को वीडियो भेजा था। इसके बाद उन्होंने दो करोड़ रुपए मांगने के लिए ब्लैकमेल किया था। इस बारे में 24 नवंबर को हमने एसपी को

सूचित कर दिया था। साथ ही, विभागीय अधिकारियों को बता दिया था। इसके बवजूद जब 5 दिसंबर को वीडियो वायरल हुआ तो 6 दिसंबर को सरकार ने केवल व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर सस्पेंड कर दिया। ना कोई नोटिस दिया और ना ही किसी तरह की जांच कराई गई।

इस पर हाईकोर्ट जस्टिस ने पूछा कि जब आपके अधीनस्थ अधिकारी को ठेकेदार के सुसाइड के बाद 9 नवंबर को ही वीडियो की जानकारी मिल गई थी और आपको पता चल गया, फिर आपने विभाग को सूचना क्यों नहीं दी। दीक्षित के अधिवक्ता ने कहा कि हमने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और आबकारी आयुक्त को बताया था। साथ ही, 24 नवंबर को ही एसपी को बताया था। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने पोल खोली दी। सरकारी वकिल ने कहा कि इन्होंने भले ही एसपी को 24 नवंबर को बताया हो लेकिन शासन स्तर पर उच्च अधिकारियों को 6 दिसंबर को ही बताया था। इसी के बाद इन्हें सस्पेंड किया गया था। जबकि इन्हें वीडियो की जानकारी 9 नवंबर को ही आ गई थी। इन तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि इसमें कुछ फिशी (संदिग्ध) लग रहा है। यदि आपको जानकारी 9 नवंबर को ही आ गई थी तो शासन स्तर पर यह बताना था। यह सामान्य मामला नहीं है, एक ठेकेदार द्वारा सुसाइड किया गया है। भले ही वह वीडियो पहले बना था और व्हाट्सएप पर 5 दिसंबर को आया, लेकिन यह गंभीर मामला है। साथ ही, इसमें रिश्वत के गंभीर आरोप लगे हैं। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि हमारे पास वीडियो व अन्य सामग्री है और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के लिए सस्पेंड कर ग्वालियर अटैच किया गया है। उनकी जगह अन्य को प्रभार दिया गया है और उन्होंने वहां जॉइन भी कर लिया है। जांच को लेकर खुलासा नहीं कर सकते हैं, वह गोपनीय है। इस पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक : **अक्षय तिवारी** द्वारा मेसर्स डी.बी. कार्प लिमि. 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड़, इंदौर (मप्र)- 452008 से मुद्रित एवं 5/6, नार्थ राजमोहल्ला (गुरूद्वारे के सामने), इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। **आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650**
सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र केवल इंदौर रहेगा। समाचार पत्र में व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित खबर एवं आलेख के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।